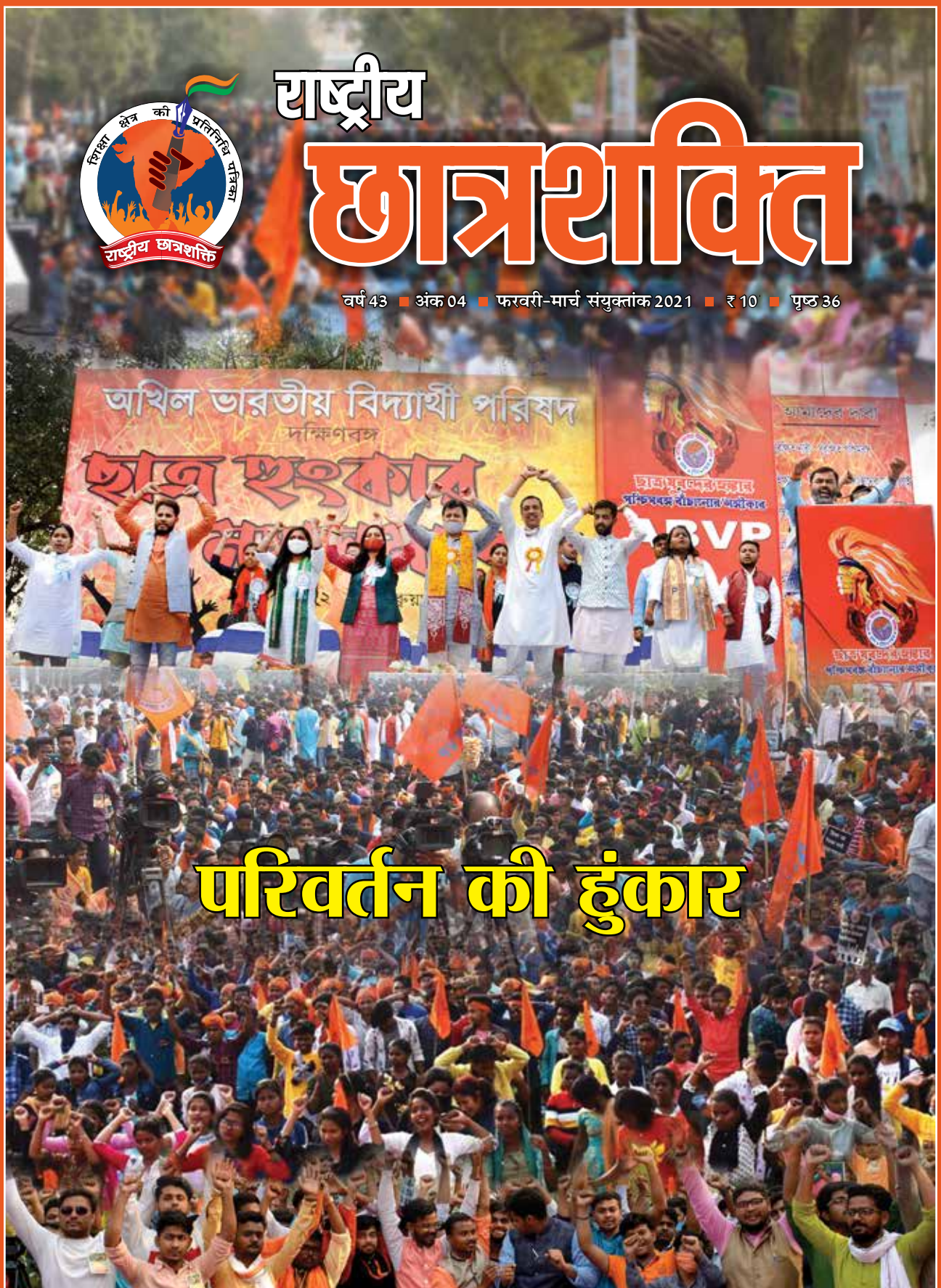

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 43 ■ अंक 04 ■ फरवरी-मार्च संयुक्तांक 2021 ■ ₹ 10 ■ पृष्ठ 36

परिवर्तन की हुंकार

परिषद् गतिविधियां

उज्जैन : कार्यालय उदघाटन समारोह के दौरान परिषद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते म. प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंचासीन रा.स्व. संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत समेत अन्य पदाधिकारी एवं इनसेट में अभाविप का नवनिर्मित भव्य कार्यालय

हैदराबाद : मनमानी शुल्क वसूली करने वाले महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने एवं छात्रों को शुल्क में छूट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 43, अंक 04
फरवरी –मार्च संयुक्तांक, 2021

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

05 अभाविप ने भरी परिवर्तन की हुंकार

पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध, हिंसा, बेरोजगारी, बलात्कार और अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में 22 फरवरी को कोलकाता एवं 24 फरवरी को सिलीगुड़ी में विशाल छात्र हुंकार महासमावेश का आयोजन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में बंगाल के युवाओं ने भाग लिया। कोलकाता और सिलीगुड़ी की सड़कें छात्र हुंकार से गूंज...

संपादकीय	04
रा.स्व.संघ को समझना है तो उसके सेवा भाव को समझना होगा: योगी आदित्यनाथ	09
FILLING THE COFFERS WITH A STRUCTURAL TWIST	10
स्वामी विवेकानंद और नेताजी का जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा : आकांत	11
विद्यार्थियों के अंदर की प्रतिभा को निखारने का मंच है 'स्वयंसिद्ध 2021' : श्रीवास्तव	12
ABVP PRESENTS A MEMORANDUM TO THE UGC CHAIRMAN FOR IMPLEMENTATION OF NEP	13
बांग्लादेशी घुसपैठ का केन्द्र बना पश्चिम बंगाल	14
उत्तर बंग के अभाविप कार्यालय का है अंतरराष्ट्रीय महत्व : सुनील आंबेकर	16
पुलवामा के बलिदानी वीरों की याद में तिरंगा रैली	17
ABVP SUBMITS A LETTER OF SUGGESTION TO THE UNION MINISTER ON THE PROPOSED NATIONAL SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION POLICY (STIP– 2020)	18
अवध : चौरी–चौरा शताब्दी वर्ष पर अभाविप ने आयोजित किए कई कार्यक्रम	19
चौरी–चौरा में मालवीय: एक अध्ययन	20
समाज के हर वर्ग के उत्थान में योगदान दे रहे हैं परिषद कार्यकर्ता : होसबाले	22
INITIATE ACTION AGAINST COLLEGE MANAGEMENT, REDUCE FEE BY 50 % : ABVP	23
EDUCATIONAL INSTITUTIONS SHOULD BE OPENED WITHOUT DELAY, ONE YEAR SHOULD BE EXTENDED FOR RESEARCH SCHOLARS: ABVP	24
अध्ययन दल की रिपोर्ट में खुलासा, किसान आंदोलन पर वामपंथियों का कब्जा	25
आखिर उजागर हो ही गया किसान नेताओं का असली चेहरा	26
अपने रास्ते से भटक चुका है किसान आंदोलन	28
देश से बढ़कर कुछ नहीं: निखिल रंजन	30
विलक्षण प्रतिभाओं को सम्मानित कर गौरवान्वित होता भारतीय समाज	31
परिचर्चा/ दिल्ली की हिंसा संयोग है या सुनियोजित षड्यंत्र	33

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

26 जनवरी को किसान नेताओं के आश्वासन के बावजूद लाल किले पर जो हुआ वह अस्वीकार्य है। घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसानों के इस आंदोलन में अराजक तत्वों की घुसपैठ हो चुकी है और उन्हें उन स्रोतों से सहायता प्राप्त हो रही है जो देश में शांतिव्यवस्था को चुनौती देते रहे हैं।

घटना की आशंका तभी से बलवती होने लगी थी जब आंदोलनस्थल पर भिंडरवाले और शाहीनबाग हिंसा में गिरफ्तार लोगों को छोड़े जाने संबंधी पोस्टर दिखायी देने लगे थे। पुलिस ने अभूतपूर्व संयम दिखाते हुए शरारती तत्वों का मंसूबा पूरा नहीं होने दिया। घटनाक्रम बताता है राष्ट्रीय संवेदना को चोट पहुंचाने के लिये ही अराजक तत्वों ने गणतंत्र दिवस का दिन चुना था। पुलिस की पड़ताल में इसकी पुष्टि हो रही है।

अदृश्य शक्तियों की सहायता से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले इन लोगों ने किसान आंदोलन के प्रति जनसामान्य की सहानुभूति को काफी हद तक कमजोर किया है। किसान खुद भी इस आंदोलन से दूर होते नजर आ रहे हैं तो इसका सीधा कारण है कि भारत का मूल चरित्र व्यक्तिगत अथवा सामूहिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का है। सैकड़ों हजारों वर्षों के सामूहिक चिंतन में से जो "स्व" का भाव उत्पन्न हुआ है उसे क्षणिक आघात नहीं डिगा सकते।

"स्व" की पहचान और उससे भारतीय मनोजगत की संबद्धता का ताजा प्रमाण है अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर। जब न्यायालय से इस संबंध में निर्णय आया तो पूरे देश ने इसका स्वागत किया और जो लोग यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि इसकी आड़ में भारी हिंसा को भड़काया जा सकेगा, उन्हें निराश होना पड़ा। कोविड-19 के प्रकोप के चलते आर्थिक गतिविधियों के ठप होने के बावजूद जिस प्रकार पूरे देश से मंदिर निर्माण के लिये आर्थिक समर्पण प्राप्त हो रहा है वह बताता है कि भारत का समाज जिस भावभूमि पर जीता है वह सारे संसार से अलग है और भौतिक उपभोग के आधिक्य के पैमाने पर सुख को मापने वाले लोग इसकी अनुभूति भी नहीं कर सकते।

अभाविप रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के आन्दोलन में 80 के दशक से ही सहभागी रही। वह मानती रही कि राष्ट्रमंदिर के निर्माण की आधारशिला राम मंदिर का निर्माण है। आज जब सारी विघ्न-बाधाओं को पार कर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, परिषद के सपने और सिद्धांत दोनों के सत्य सिद्ध होने का अवसर है।

मकरसंक्रांति के बाद उत्तरायण में सूर्य का प्रवेश मंगलकारी माना जाता रहा है। भारत के उत्तरी सीमांत से चीन के सैनिकों की वापसी तथा पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर सहमति एक सुखद संदेश की भाँति आयी है। कोविड की वैक्सीन ने न केवल भारतीय वल्कि पूरे विश्व को सुरक्षा का अहसास कराया है वहीं भारत की वैज्ञानिक क्षमता को विश्वपटल पर स्थापित करने का काम भी किया है।

कोविड का प्रभाव जैसे-जैसे कम होता जा रहा है, संगठनात्मक गतिविधियों की भी गति बढ़ रही है। गत मास मे हुए बहुविध कार्यक्रमों के विवरण को संजोये यह अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

हार्दिक शुभकामना सहित,

आपका,
संपादक

अभाविप ने भरी परिवर्तन की हुंकार

| अजीत कुमार सिंह |

पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध, हिंसा, बेरोजगारी, बलात्कार और अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में 22 फरवरी को कोलकाता एवं 24 फरवरी को सिलीगुड़ी में विशाल छात्र हुंकार महासमावेश का आयोजन किया गया। कोलकाता में लगभग 20 हजार तो सिलीगुड़ी में 18 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कोलकाता और सिलीगुड़ी की सड़कें छात्र हुंकार से गूंज उठी, इस रैली को देखकर लग रहा था मानों बंगाल में परिवर्तन की बयार बह रही है। प्रदर्शन के बाद आयोजित हुए जनसभा में वक्ताओं ने प्रदेश में बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा, तस्करी, बढ़ती बेरोजगारी, कुशासन एवं तुष्टीकरण को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। रैली में आये युवाओं का कहना था कि ममता सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वैचारिक विरोधियों की हत्या यहां पर आम बात हो गई है। महिलाओं के साथ दुराचार और छेड़-छाड की घटनाओं में वृद्धि हुई है। महिला मुख्यमंत्री के राज में महिला ही सुरक्षित नहीं है।

अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि उन्नीसवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक, यदि कोई छात्र भारत के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता था तो वह था कलकत्ता विश्वविद्यालय लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल इतना पीछे रह गया ? उन्होंने कहा

कि वामपंथियों की हिंसा और कुव्यवस्था के त्रस्त होकर बंगाल की जनता ने बड़े ही आशा के साथ ममता दीदी को बंगाल की सत्ता सौंपी थी। उन्हें लगा था कि दीदी के राज में हम सुरक्षित रहेंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, महिलाएं निर्भिक होकर सड़कों पर निकलेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीदी के राज में हिंसा और बढ़ गई । राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं सरेआम होने लगी। शिक्षा, महिला सुरक्षा, राजनीतिक हत्या के कारण प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। मुस्लिम तुष्टीकरण कर राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है। भय और आतंक के कारण आज उत्तरबंग में कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं भी उनकी आधारभूत संरचना एकदम न्यूनतम है। सरकार पर निशाना साधते हुए चौहान ने कहा कि दीदी भय-अत्याचार वाला नहीं, हमें 24 कैरेट वाला सोनार बांग्ला चाहिए।

राष्ट्रीय मंत्री सप्तऋषि सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब भी कोई छात्र संगठन राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है तो उनपर हमला करवाया जाता है, क्या अब राज्य में शान्ति पूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की भी स्वतंत्रता भी नहीं है? राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। वर्ष 2016 से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में होने वाले छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगा दी गई है। ममता सरकार युवाओं को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में सामाजिक बदलाव के लिए है।

ताकि सनद रहे...

पश्चिम बंगाल में छात्रों को शिक्षक के बदले मौत मिलती है। सही पढ़ा आपने! घटना सितंबर 2018 की है। दक्षिण बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के (दारिविट) राजेश और तापस वर्मन ने विद्यालय प्रबंधन से बांग्ला और विज्ञान के शिक्षक की मांग की। बदले में उसे ऊर्दू शिक्षक मिल गया। राजेश और तापस ने कहा मुझे ऊर्दू नहीं बांग्ला और विज्ञान का शिक्षक चाहिए। बार-बार की मांग के बाद भी जब शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए पं. बंगाल की पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़े और अंत में गोली चला दी जिसमें दोनों छात्रों की मौत हो गई। उस दिन से लेकर अब तक दोनों के माता-पिता न्याय की आस में दर-दर भटक रहे हैं।

बंगाल में दो मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो राइटर्स बिल्डिंग में बैठे हुए हैं तो दूसरा सुपर मुख्यमंत्री टीपू सुल्तान मस्जिद में बैठकर फतवा जारी करता है। मुस्लिम तुष्टिकरण और सत्ता मद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी चूर है कि दुराचार के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पैसे की बोली लगाई जाती है।

- निधि त्रिपाठी
(राष्ट्रीय महामंत्री, अभाविप)

पश्चिम बंगाल में जब भी कोई छात्र संगठन राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है तो उनपर हमला करवाया जाता है, क्या अब राज्य में शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की भी स्वतंत्रता भी नहीं है?

- सप्तऋषि सरकार
(राष्ट्रीय मंत्री, अभाविप)

दक्षिण बंगाल प्रांत मंत्री सुरंजन सरकार ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि आज का बंगाल अपनी सहनशीलता खो चुका है। बंगाल में टी.ई.टी कांड, एसएससी घोटाला जैसी घटनाएं हो रही हैं। हम एक भव्य बंगाल का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा बंगाल जो न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में आगे होगा। वहीं पूर्व क्षेत्र के सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री अपांशु शेखर सील ने कहा कि इस बार बंगाल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भूमिका अग्रणी रहेगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि राज्य में बंगाल की बेटियों की जो मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे पातीं ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में बैठे रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि इन दिनों विधानसभा चुनाव पूर्व एक नया नारा दिया गया है। हमें चाहिए बंगाल की बेटी। नारा देने वाले नेताओं को बंगाल की बेटियों से भी जाकर जानकारी लेनी चाहिए, क्या वह बंगाल की बेटी को सत्ता में बैठे देखना चाहते हैं। जिस बंगाल की बेटी को 34 वर्षों के कुशासन से मुक्ति दिलाकर बंगाल के बेटे बेटियों ने उन्हें सत्ता सौंपा आज सत्ता में बैठने के बाद युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी।

ममता बनर्जी पर हमला करते हुए महामंत्री निधि ने कहा कि राज्य में दो मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो राइटर्स बिल्डिंग में बैठे हुए हैं तो दूसरा सुपर मुख्यमंत्री टीपू सुल्तान मस्जिद में बैठकर फतवा जारी करता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण और सत्ता मद में मुख्यमंत्री इतनी चूर है कि दुराचार के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पैसे की बोली लगाई जाती है। हमें ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिसे श्रीराम के नाम से नफरत होती हो। हमें ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जिसके राज्य में मानव तस्करी दुराचार और राजनीतिक हत्या अपने प्रकाष्ठा को पार कर जाए। हमें ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो माने जयंती पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाएं। हमें ऐसी मुख्यमंत्री

अभाविप की पांच महत्वपूर्ण मांगे -

- सुरक्षित नारी - सुरक्षित पश्चिम बंगाल
- सबको रोजगार का अवसर मिले
- सस्ती-सुलभ व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- हिंसा मुक्त और गणतांत्रिक अधिकार युक्त पश्चिम बंगाल
- मुस्लिम तुष्टिकरण बंद हो

वामपंथियों की हिंसा और कुव्यवस्था के त्रस्त होकर बंगाल की जनता ने ममता दीदी को बंगाल की सत्ता सौंपी थी। उन्हें लगा था कि दीदी के राज में हम सुरक्षित रहेंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, महिलाएं निर्भिक होकर सड़कों पर निकलेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीदी के राज में हिंसा और बढ़ गई ।

- आशीष चौहान
(राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अभाविप)

विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन महज सत्ता परिवर्तन का नहीं है। विद्यार्थी परिषद का संकल्प पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक जागरण का है । हम पश्चिम बंगाल में उसी विवेकानंद के गुणों को वापस लाना चाहते हैं जिन्होंने बंगाल के आधार पर दुनिया को जगाया ।

- श्रीनिवास
(राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री, अभाविप)

नहीं चाहिए जिसके राज्य में 300 परिवारों के बीच 25 मुस्लिम परिवार के लिए वह 300 हिंदू परिवारों के धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाए। हमें ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जिसके राज्य में 8 लाख बेरोजगार छात्र छात्राओं में मात्र एक लाख को बरोजगारी भत्ता देती हो। हमें ऐसे मुख्यमंत्री को बदलना होगा जिन्होंने 20,000 से अधिक रोजगार वाले उद्योग को बंगाल के बदले बांग्लादेश में ले जाने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि शैक्षिक परिसरों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। शैक्षणिक माहौल मांगने पर ऐसे

छात्र छात्राओं को बाहर के गुंडों से पिटवाया जाता रहा हो। हमें बंगाल में ऐसी बेटी चाहिए जो सुरक्षित नारी सुरक्षित पश्चिम बंगाल, शिक्षा के बदले भिक्षा नहीं दे, राजनीतिक हिंसा से बंगाल को मुक्त करवाएं गणतंत्र का वास्तविक अधिकार सभी को दें शिक्षा के आधार पर आधारभूत सुविधाएं बंगाल के प्रत्येक प्रखंड में मुहैया करवाएं शिक्षा से जुड़े उद्योगों की स्थापना करें और अपनी मातृभाषा के शिक्षक मांगने पर उन्हें पुलिस की गोलियों से ना भूनवाए।

प्रदेश मंत्री (उत्तर बंग) विराज बिस्वास ने कहा कि 35 वर्ष के वाम कुशासन और 10 वर्ष के तृणमूल के कुशासन ने बंगाल के बंगाली चिन्ताभावना और बुद्धि को कोल्डस्टोरेज में बन्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य का विश्वविद्यालय परिसर सब्जी मंडी में बदल गया है और प्रत्येक पाठ्यक्रम(कोर्स) का मूल्य निर्धारण कर दिया गया है।

राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि हमारा यह आंदोलन महज सत्ता परिवर्तन का नहीं है एक माइंड सेट करने का आंदोलन है, इसलिए विद्यार्थी परिषद का संकल्प इस प. बंगाल के सांस्कृतिक जागरण का संकल्प है । यह प. बंगाल उसी विवेकानंद के गुणों को वापिस लाना चाहता है जिन्होंने बंगाल के आधार पर दुनिया को जगाया, यह प. बंगाल नेताजी के उसी जय हिंद के नारे को जागृत करना चाहता है और यह प. बंगाल जागृत करना चाहता है उसी वंदे मातरम की भूमि को,जो भारत की क्रांति का बीज मंत्र हो गया।

अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री विनीता इंदवार ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं को अपने नाम से जारी रख रही हैं। जनजाति समाज के विकास उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं लिया गया है।

क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोविन्द नायक ने कहा कि अभाविप हमेशा इसी बात पर विश्वास करती है कि राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है, समाज परिवर्तन के लिए व्यक्ति परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन हो सकता है।

गौरतलब है कि अभाविप के द्वारा विगत तीन माह से बंगाल हिंसा के खिलाफ ब्लॉक स्तर से लेकर जिला केन्द्रों तक अनेक प्रदर्शन किये गये। जिला केन्द्रों में सफल प्रदर्शन के बाद 22 फरवरी को अभाविप दक्षिण बंगाल द्वारा कोलकाता में विशाल छात्र रैली का आयोजन किया गया था जिसमें बीस हजार से अधिक छात्र- छात्राओं ने भाग लिया था। कोलकाला रैली के बाद 24 फरवरी को उत्तर बंगाल द्वारा सिलीगुड़ी छात्र हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों - हजार की संख्या में छात्रों ने भाग लिया। रैली में छात्रों के साथ-साथ आम जन का भी उत्साह चरम पर था। ■

रा.स्व.संघ को समझना है तो उसके सेवा भाव को समझना होगा: योगी आदित्यनाथ

सुनील आंबेकर की पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र' का हुआ लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रा.स्व. संघ) को समझने के लिए उसके सेवा भाव को समझना होगा। उन्होंने कहा कि संघ एक ऐसा संगठन है, जो बिना किसी सरकारी सहयोग के सेवा कार्य करता है। मुख्यमंत्री ने ये बातें 26 फरवरी को ऊ.प्र. की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं रा.स्व.संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर द्वारा लिखी पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र' के लोकार्पण समारोह में कही।योगी ने कहा कि मात्र एक पुस्तक नहीं है बल्कि एक दृष्टि है। बूंद और शक्कर के मिलन की तरह ही संघ अपनी उपस्थिति का अहसास कराता रहा है। शक्कर की तरह इसे हर कोई अहसास करता है। यही इस पुस्तक में भी दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में हर लोग चिंतित थे कि कैसे परिस्थितियों को संभाला जाय ? ऐसे में संघ पहला संगठन था, जो लोगों को घर-घर जाकर सहायता पहुंचाने के लिए आगे आया था।

रा. स्व. संघ के सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इस अवसर पर कहा कि संघ के बारे में मिथ्या प्रचार ज्यादा हो गया था। इसके बारे में बिना जाने बोलने वालों की संख्या ज्यादा हो गयी थी। संघ प्रारंभ हुआ एक संगठन के रूप में लेकिन डॉ. हेडगेवार जी ने पहले ही कहा कि यह कोई नया काम नहीं है। यहां मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। नाम भी इसे बाद में दिया गया। संघ एक जीवन दृष्टि है, यह एक अनुभव है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति का विचार या मत संघ नहीं होता। यहां समूह का मत होता है।

पूर्व में स्तम्भकार नरेन्द्र भदौरिया और गोविंद वल्लभ पंत संस्थान के निदेशक बद्री नारायण ने पुस्तक के बारे में विस्तार से बताया। पुस्तक के लेखक सुनील आंबेकर ने कहा कि वह विश्वविद्यालयों में जाते थे तो बहुत सारी जिज्ञासाओं के बारे में पता चलता था। हमें यह भी पता चला कि एक ऐसी पीढ़ी भी है, जिन्हें पूरी दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है और उनके तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं। विदेशों में रह रहे भारतीयों में यह विचार देखा गया कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं। इसी विचार के बाद हमने पुस्तक के बारे में विचार किया और संगठन के प्रति उठ रहे जिज्ञासाओं के समाधान करने का हमने किताब के माध्यम से प्रयास किया। इस किताब में संघ को समाहित नहीं किया जा सकता लेकिन मैं जो भी समझ पाया, उसे समझाने का प्रयास किया।

गौरतलब है कि सुनील आंबेकर ने पूर्व में 'द आरएसएस-रोडमैप्स फॉर द 21 सेंचुरी' नामक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी

थी, जिसका वर्ष 2019 में संघ प्रमुख मोहन राव भागवत ने लोकार्पण किया था। 26 फरवरी को जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, वह अंग्रेजी पुस्तक का ही हिन्दी रुपान्तरण है। इसका हिंदी में अनुवाद डा. जितेंद्र वीर कालरा ने किया है। प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। लोकार्पण कार्यक्रम में रा.स्व. संघ के सह सरकार्यवाह डॉ कृष्ण गोपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल, अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल, संघ के संयुक्त क्षेत्र प्रचार प्रमुख कृपाशंकर, वरिष्ठ प्रचारक मनोजकांत,अवध प्रान्त के प्रचार प्रमुख डॉ. अशोक दुबे, अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री रमेश गड़िया, प्रांत संगठन मंत्री घनश्याम शाही और अवध प्रान्त के सह प्रान्त प्रचार प्रमुख दिवाकर अवस्थी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रभात प्रकाशन के प्रमुख प्रभात कुमार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचार प्रमुख नरेंद्र सिंह ने किया। ■

Filling the Coffers with a Structural Twist

| Purvi Mundhra |

With the plans of the government to boost the economic growth not just only to the pre-pandemic levels but aiming for a better performance requires a structural change in the fiscal policy and the way towards it is being paved by the new 'Public Sector Policy'.

With the outbreak of the COVID-19 pandemic, the government had to put its highly ambitious Rs 2.1 tn disinvestment plans of FY21 in the backseat. It has raised less than 3% of the budgeted revenues from disinvestment in FY21, given the fact that it was a vital element in the government's strategy to keep its fiscal deficit under check. However to revive and boost the disinvestment sentiments in the country, the government has released a new 'Public Sector Enterprise' policy under which only 4 strategic sectors would be retained with atleast one PSU in the four broad categories while the remaining CPSEs will be privatized/merged/closed. However, in the non-strategic sectors, all the CPSEs will be privatized.

This is clearly a structural and directional shift in the policy making which bodes well with the government's idea of 'Minimum Government, Maximum Governance'. Plans of government for higher expenditure calls for a better money management with the fiscal deficit as a percentage of GDP being pegged at 9.5% for the FY21, highest ever. Indeed, unprecedented times call for extraordinary measures. Currently, the key challenge that the country is facing is to enhance gross capital formation which therefore requires the private sector investments to rise. With the plans of massive expenditure in infrastructure, the risk of crowding out of private expenditure increases. Therefore, to negate this impact, it becomes crucial to bring in private sector expenditure where the revenue streams are flowing in.

Privatizing the public sector enterprises would lead to overall enhancement of total factor productivity. Research conducted by OECD had suggested that productivity in public firms are 10% lower than the private sector, when the state and industry specific factors are not controlled. The Public Sector Enterprises Survey showed that in FY19, 70 CPSEs recorded total losses of Rs 316 billion. BSNL, MTNL and Air India accounted for 84% of the losses. Similarly, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) in 2018, shows that the government had invested more than Rs 3.5 tn in the shares of 420 government companies and corporations. The market value of shares held by the government in 42 listed PSEs was Rs 13.63 trillion.However, research findings suggest that financial and operational performance of CPSEs have improved significantly after disinvestment and privatization therefore positively impacting the performance of the CPSEs.

As the world becomes a global village, privatization as a policy norm seems to countermand political compulsions as an instrument for achieving competitive efficiency and resource optimization. Reallocation of assets and functions from the public sector to the private sector play a vital role for economic growth.

***Author** is an Economic Research Associate in a leading corporate firm*

All views are personal. ■

स्वामी विवेकानंद और नेताजी का जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा : आकांत

स्वामी विवेकानंद जयंती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने युवा सप्ताह के रूप में मनाया। युवा दिवस के उपलक्ष्य पर अभाविप द्वारा देशभर में मैराथन, क्वीज प्रतियोगिता, खेल, रंगोली, रक्तदान शिविर, संगोष्ठी समेंत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये। अभाविप, हरियाणा के द्वारा सोनीपत में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया।

सोनीपत युवा महोत्सव में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि आज का छात्र कल का नागरिक नहीं अपितु आज का ही नागरिक है। इसलिए आज का छात्र अपनी पढाई के साथ-साथ देश और समाज की समस्याओं को भी समझे और उनके समाधान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्री आकांत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 वर्ष आयु जीये लेकिन इतने कम आयु में ही उन्होंने विश्वभर में भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया। स्वामी जी से प्रेरित नेता जी ने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद और नेता जी का जीवन हर युवा लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती ने कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढाया है।

सोनीपत महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए विभाग संगठन मंत्री सुनील भारद्वाज ने बताया कि इस महोत्सव में 10 विभिन्न कार्यक्रम यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कबड्डी, योग, रस्साकसी, ताईक्वांडो, एथलेटिक्स, पौधरोपण और मलखंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें 53 शिक्षण संस्थानों के 618 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन कर्ता और मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकांत उपस्थित रहे वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो० राजेंद्र कुमार अनायत ने की। विशिष्ठ अतिथि के रूप में कविता जैन (पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार), उपस्थित रही। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ विनय कपूर इत्यादि ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। ■

गुवाहाटी : कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, असम प्रांत के चराईदेऊ जिले में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें वहां के छात्रों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अभाविप असम के प्रांत सह मंत्री खूनलाई मोहन ने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। अभाविप युवाओं का संगठन है। उन्होंने कहा कि युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे आयोजन किये जाते रहे हैं। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा चराईदेऊ जिला के सोनारी नगर शाखा द्वारा जिला स्तरीय अंतर विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 विद्यालय के 210 छात्रों ने सहभाग लिया। ■

विद्यार्थियों के अंदर की प्रतिभा को निखारने का मंच है 'स्वयंसिद्ध 2021' : श्रीवास्तव

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय छात्रा सह प्रमुख डॉ. उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्रों के अंदर की प्रतिभा को निखारने एवं उसे उचित मंच देने का कार्य कर रही है। परिषद का मानना है कि समाज का उत्थान विद्यार्थियों के द्वारा ही किया जा सकता हैं। उन्होंने कहा कि अभाविप, छात्र हितों के लिए केवल आंदोलन ही नहीं करती बल्कि अपने रचनात्मक कार्यक्रम के जरिये छात्रों की प्रतिभा को निखारती भी है। 'स्वयंसिद्ध 2021' कार्यक्रम भी इसी का हिस्सा है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के अंदर की प्रतिभा को निखारने का मंच है। डॉ. श्रीवास्तव ने ये बातें अभाविप, गोरक्ष द्वारा आयोजित 'स्वयसिद्ध 2021' कार्यक्रम के उदघाटन सत्र में कहीं । बता दें कि गोरखपुर में विद्यार्थी परिषद द्वारा युवा पखवाड़ा के तहत छः दिवसीय 'स्वयंसिद्ध 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

विशेष आमंत्रित सदस्य (राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद, अभाविप) डॉ. राजशरण शाही ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की स्थापना के पीछे का उद्देश्य भारत को पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन करना है। यह सब छात्रों के बिना असंभव है। जब नेपाल, बाढ़ के भीषण विभीषिका को झेल रहा था तब परिषद के कार्यकर्ताओ ने सबसे पहले वहा पर पहुंच कर बाढ़ग्रस्त लोगो की मदद की। डॉ. शाही ने प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं अभाविप की प्रांत अध्यक्ष प्रो.सुषमा पांडेय ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी परिषद शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने के साथ-साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य करती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का उद्देश्य "शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिये" होना चाहिए। वायु का उल्टा युवा होता है, इसलिए युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देते हुए राष्ट्रनिर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए शक्ति ने कहा कि 18-24 जनवरी तक गोरखपुर महानगर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के परिसर में 'स्वयंसिद्ध 2021' आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 13 प्रकार (एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, मैराथन, बैडमिंटन, भाषण, शतरंज, पोस्टर मेकिंग, मेंहदीं, समान्य ज्ञान एवं निबंध लेखन) की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1800 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ■

अलीगढ़ में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन

अभाविप, ब्रज प्रांत द्वारा अलीगढ़ में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शहर के अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार मालपाणी थे। श्री मालपाणी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों एवं युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो इसे पाने के लिए खूब मेहनत करें साथ ही राष्ट्रहित के लिए हमेशा तत्पर रहें। देश और समाज के लिये भी कार्य करें जिससे हमारा देश पुनः विश्व गुरू बन सके। अभाविप के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ पुष्पेंद्र पचौरी ने कहा इस देश को आजादी दिलाने में युवाओं की महत्ती भूमिका रही है। वर्तमान समय में देश कठिन चुनौतियों से गुजर रहा है, कुछ लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद ऐसे ही नापाक मंसूबों के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब देश में ना कोई जिन्ना पैदा होगा न कोई पाकिस्तान। हम समाज व देश के लिये कार्य करें भारत माता की जय जयकार करें। महानगर उपाध्यक्ष सौरभ सेंगर ने कहा हम अपनी मातृभूमि की सेवा करें। ■

ABVP presents a memorandum to the UGC Chairman for Implementation of NEP

A delegation of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) office bearers called on the University Grants Commission (UGC) Chairman D.P. Singh and presented a memorandum of suggestions regarding the implementation of the recently unveiled National Education Policy 2020. The suggestions were solicited after extensive interactions with numerous stakeholders and relate to issues ranging from holistic learning and institutional research to integrated higher education system and promotion of Indian knowledge systems. Among other things, the recommendations are aimed at advancing equity and inclusive learning in higher education as well as promoting India as a leading global study destination.

ABVP has recommended a revision of the IIT curriculum, focus on interdisciplinary research and novel methodologies for the integration of humanities and STEM (Science, Technology, Engineering and Math) at the undergraduate level, identification of select public and private universities as Research Institutions, which should mandatorily have in-house corpus funds in the form of University Research Fund, to be utilised for the purpose of research and promotion of innovation, start-up incubation with guidance from the NEP mandated National Research Foundation.

For inclusive higher education, ABVP has recommended greater cooperation between the Ministries of Education, Tribal Affairs and Social Welfare for the institution of special programs for the tribal, Dalits, and differently-abled students, collectively described as the Socially and Economically Disadvantaged Groups in the NEP 2020. More Kasturba Gandhi BalikaVidyalayas in every district along with the utilisation of the Gender Inclusion Fund primarily for the development of transport and health facilities for female and transgender students in rural areas has also been one of the major recommendations of ABVP.

Introduction of the 'Early Career Award' for excellence in research, converting temporary, ad hoc and contractual teachers' appointments into permanent, inviting top 100 global educational institutions to set up campuses in India as well as calling on the leading Indian educational institutions to set up campuses abroad.

Promotion of Indic-research and programs related to the study of uniquely Indian cultural traditions including textiles and cuisines, by way of Endowed Fellowships as well as by instituting Chairs supported by national and international philanthropic initiatives, setting up the Indology Research Foundation for promoting research and learning in Indian Philosophy, Indian Sciences, and Indic knowledge systems like Yoga and Ayurveda.

NidhiTripathi, National General Secretary, ABVP, said, "While the NEP 2020 is a very comprehensive document in itself and capable of addressing the multi-dimensional challenges in a satisfactory manner, based on our wide interaction with all the stakeholders in the field of education, we felt the need to apprise the Expert Groups of additional suggestions which could be useful in making the implementation of NEP more impactful and effective. We are hopeful that the suggestions will be factored in and implemented in the best interests of India's student community." ■

बांग्लादेशी घुसपैठ का केन्द्र बना पश्चिम बंगाल

| श्रीनिवास |

स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व व आंदोलन के दौरान सम्पूर्ण भारत का आध्यत्मिक एवं वैचारिक जागरण का केंद्र बंगाल की भूमि रही है। भारत के अनेक मूर्धन्य विचारक इसी मिट्टि में उत्पन्न हुए, जिन्होंने न केवल भारत अपितु वैश्विक जगत में भारत के वास्तविक स्वरूप को पहचान दिलाई है। पश्चिम बंगाल, भारत का ऐसा राज्य है जो विभाजन के बाद से ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ कई समस्याओं से जूझता रहा है। न केवल भौगोलिक सीमाओं के अस्पष्ट विभाजन अपितु बांग्ला भाषा की समानता के कारण भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती रही है। भाषाई भावनाएं हमेशा सिर चढ़कर बोलती रही है,जो कभी-कभी राष्ट्र की अखंडता के लिये भी खतरा बनी है।

जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से बंगाल उर्वरा भूमि रही है परंतु दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे इस भारत केंद्रित ऊर्जा भूमि को मानो ग्रहण लगना प्रारम्भ हो गया। सम्पूर्ण देश के साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में जब भारत के बाहर से आये वामपंथी विचारधारा के लोगों का दबदबा बढ़ने लगा तो उन्होंने ऐसे ऊर्जा केंद्रों को अपना निशाना बनाना शुरू किया, जहां से समाज को एक सकारात्मक व प्रभावकारी दिशा मिलती थी। जो एक तरह से राष्ट्र के नाभि केंद्र थे। इन्ही नाभि केंद्रों में से एक पश्चिम बंगाल को भी वामपंथियो ने अपनी वैचारिक यात्रा की प्रयोगशाला बनाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्थापित विचार या मान्यताओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न करना, समाजिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल बना कर आंदोलन खड़े करना व धीरे-धीरे राजनीतिक शक्ति अर्जित करना वामपंथ की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। यह विचित्र मानसिकता है कि सार्वजनिक व्यवहार में ये सत्ता से दूर रहने का स्वांग रचते है,परंतु वास्तव में जनवादी क्रांति के द्वारा सत्ता पर ही काबिज होना प्रमुख लक्ष्य होता है। भारत के वामपंथियो ने पश्चिम बंगाल में भी यही किया। क्योंकि पश्चिम बंगाल भारतीयता को पुष्ट करने वाला प्रमुख व महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए एक व्यापक षड्यंत्र के तहत इन्होंने इसी राज्य को अपनी क्रीड़ा स्थली के रूप में चुना।

वामपंथी विचारधारा को पल्लवित पोषित होने के लिये जितने कारक चाहिए । बंगाल की परिस्थितियों में वह भी इनको मिलते गए। इनके निरन्तर किए जा रहे प्रयासों से 60 के दशक में ये मंसूबो में सफल हो गए। राजनीति में कांग्रेस का पतन एवं वामपंथ का वर्चस्व स्थापित होने लगा। जैसे ही इनको सत्ता मिली, इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जहां एक ओर सत्ता के द्वारा सभी शक्तियों पर एकाधिकार स्थापित किया, वहीं दूसरी ओर सामंती विरोध के नाम पर नक्सल जैसा आंदोलन खड़ा कर दिया।

देखते - देखते पश्चिम बंगाल एक ऐसी अराजक व हिंसक राजनीति का शिकार होता गया, जिसकी कल्पनी किसी ने नहीं की थी। अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया जाने लगा। समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीयता कमजोर होने लगी। लोकतांत्रिक मान्यताएं शिथिल पड़ने लगी। यहां तक कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को भी प्रायः समाप्त कर दिया। बंगाल राजनीतिक विरोधियों की हत्याओं के रक्त रंजित दौर साक्षी बनने लगा। बंगाल में एक नई धारा यानी गोली व बम की धारा बहने लगी। विकास के सभी रास्ते बंद होने लगे। शिक्षा का स्तर गिरने लगा। महिलाओं, वंचितो, पिछडो, वनवासी व गरीबों की हालत दयनीय होने लगी। प. बंगाल में अब कानून का राज नहीं अपितु कम्युनिस्ट कैडर का राज स्थापित हो गया। इतना ही नहीं बल्कि एक बहुत ही खतनाक खेल भी इनलोगों ने खेला। अपनी सत्ता व दबदबा बनाये रखने के लिये देश की अखंडता को भी दांव पर लगा दिया।

अपने तीन दशक से अधिक के शासन में वामपंथियो ने बंगाल को हर दृष्टि से खोखला बना दिया। जो बंगाल हिंदुत्व का प्राणतत्व था, राष्ट्र की स्वतंत्रता का बीज मंत्र

जहां प्रस्फुटित हुआ, भारत की आध्यत्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा, उसी बंगाल को कम्युनिस्ट की देशद्रोह नीति ने नोच डाला। वन्देमातरम जैसे अमर गीत की उद्घोषणा जिस जमीन पर हुई, आज वही जमीन अपने अस्तित्व खोज रही है।

भारत विभाजन के समय मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान बन गया परंतु पाकिस्तान के आंतरिक द्वंद्व के चलते 70 के दशक में भाषाई युद्ध शुरू हो गया और भारत की सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुय पूर्वी पाकिस्तान की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान की क्रूरता से मुक्त करवाकर बांग्लादेश को अस्तित्व में ला दिया। 1971 के युद्ध में दुनिया में एक नया देश बना बांग्लादेश। साथ में भारत की सीमाएं अब एक नए देश के साथ लगी। भारत ने बांग्लादेश को अपना मित्र देश घोषित किया। यही भारत की ऐसी भूल बनी जो आज पूरे भारत के लिये नासूर बनकर खड़ी हो गई है।

भारत ने जो मानवता के नाते बांग्लाभाषी मुस्लिमो के लिये उदारता दिखाई वही पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन के लिये एक हथियार बन गई। पश्चिम बंगाल की ज्योति बसु की कम्युनिस्ट सरकार ने राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिये मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति बनाई, जिसके चलते बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को बंगाल में लाकर बसाया जाने लगा। बंगाल के हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर करके यह जमीन दे दी गई। समाज में विरोध न हो इसलिए एक बहुत बड़ा षड़यंत्र रचा गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वामपंथियो ने यह प्रचार किया कि जो बांग्लादेशी आ रहे है वह हमारे ही बांग्ला भाषी है।

बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को न केवल बंगाल में शरण दी बल्कि उनको भूमि भी दी गई साथ ही मतदाता भी बना दिया गया, जिसका खामियाजा आज पूरा भारत भुगत रहा है। वामपंथियो के द्वारा अपनाई गई यह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति वर्तमान ममता सरकार तक जारी है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी, आज बंगाल में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है। राजनैतिक दलों व राजनेताओं के लिये यह वोटबैंक पोलटिक्स बन गई है, जिसके चलते प्रतिदिन हजारों की संख्या में अवैध घुसपैठी बंगाल में आ रहे हैं। केवल बंगाल ही नहीं अपितु आज पूरा भारत इस घुसपैठ का शिकार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तो अधिकम जिलो का डेमोग्राफिक ही बदल गया है। आज जितनी भी हिंदुओ के खिलाफ हिंसक वारदातें हो रही है उसमें इन्ही घुसपैठियों का हाथ है। पशु तस्करी से लेकर मानव तस्करी तक व समाज से लेकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ये लोग संलिप्त है।

आतंकवाद के स्लीपर सेल के रूप में भी इनकी भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल इनकी शरण स्थली बन रहा है, जिसका दुष्परिणाम देखने को भी मिल रहा है। धीरे-धीरे बंगाल की संस्कृति, उत्सव,महिलाओ की सुरक्षा, जमीन व छोटे-छोटे रोजगार के अवसरों इत्यादि सब पर संकट के बादल छा रहे हैं। भले ही यह अवैध घुसपैठ, कुछ राजनीतिक पार्टियों को तात्कालिक लाभ दिखाई देता हो परंतु आने वाले समय मे यह राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिये एक गम्भीर चुनौती जरूर बन सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठ न केवल पश्चिम बंगाल अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये खतरा है।

भारत के लोगो को यह नही भूलना चाहिए कि 1947 के विभाजन का आधार जनसंख्या ही था। एक पंथ विशेष के लोगो ने ही अलग देश की मांग की थी। जो समाज व राष्ट्र इतिहास से सबक नहीं लेते वह पुनः उसी संकट को आमंत्रित करते है। पश्चिम बंगाल के लोगो को भाषाई भावनाओं से बाहर आकर वास्तविकता को समझना पड़ेगा। यही बंगाल व भारत के हित में होगा। अब समय आ गया है, पश्चिम बंगाल का समाज विशेषकर युवा तरुणाई की कि इन वामपंथी देश द्रोहियों के पाप कर्मों को समझें व अमार बांग्ला के भाव को पुनः जागृत करें। आज जहां पूरा भारत एक नई ऊर्जा के साथ अंगड़ाई लेकर खड़ा हो रहा है, ऐसे समय में सबकी नजरें बंगाल पर टिकी है कि क्या बंगाल में भी राष्ट्र पुनर्जागरण होगा ? क्या स्वामी विवेकानंद जी की भूमि पुनः अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के गुरुतर दायित्व का निर्वहन करेगी ? पूज्य महर्षि योगी अरविंद जी की भविष्यवाणी बंगाल की आज की पीढ़ी अवश्य सुन रही होगी कि यह संक्रांति काल प्रारम्भ हो गया है, भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा और इसमें पश्चिम बंगाल की प्रमुख भूमिका होगी।

आइये इन वामपंथियो द्वारा कुंठित किये गए इस राष्ट्रीयता के प्रवाह को पुनः प्रवाहित करने में अपनी सक्रिय भूमिका बनाये। ■

(लेखक अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं।)

उत्तर बंग के अभाविप कार्यालय का है अंतरराष्ट्रीय महत्व : सुनील आंबेकर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उत्तर बंग के कार्यालय उदघाटन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रा.स्व. संघ के सह प्रचार प्रमुख एवं अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद, उत्तर बंग का यह कार्यालय कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। कई भाषा, प्रांत और मित्र देश यहां से जुड़ते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अभाविप, उत्तर बंग के इस कार्यालय का अंतर-राष्ट्रीय महत्व है। रा.स्व. संघ विचार कार्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग दो – ढाई महीने पहले हम अयोध्या गये थे। प्रभु श्रीराम के मंदिर स्थल पर मैंने देखा कुछ लोग लगातार नीचे जा रहे हैं और धक्का भी दे रहे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि यह क्या कर रहे हो तो उनलोगों ने जवाब में कहा कि यह जो मंदिर निर्माण हो रहा है, कम से कम हजार वर्ष तक टिके, इसके लिए नींव बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि संघ के कार्य में इतना समय क्यों लगता है तो उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि राम मंदिर निर्माण की तरह हमलोग भी वर्षों से देश के लिए मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं, आधार बना रहे हैं जिस पर भारत के वैभव का ध्वज हजारों वर्षों तक लहराता रहे। कार्यालय का निर्माण भी उसका एक पड़ाव है।

श्री आंबेकर ने कहा कि देश सकारात्मक भाव से आगे बढ़ रहा है, युवाओं के अंदर भी आगे बढ़ने की ललक बढ़ रही है। बंगाल के बारे में मैं क्या कहूं, आप सभी जानते हैं कि विगत 30 – 40 वर्षों में बंगाल आर्थिक रूप से कहां पहुंच गया है। देश बदल रहा है, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई हो रही है। जम्मू – कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो रहा है। हमें लगता है बंगाल को भी देश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं के आत्मविश्वास को देखकर में कह सकता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने जो 'छात्रशक्ति – राष्ट्रशक्ति' का नारा दिया था, वह साकार होते दिख रहा है। विद्यार्थी परिषद का यह कार्यालय देश और समाज के लोगों को जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा सिलीगुड़ी में आकर मैं थोड़ी भावूक हूं क्योंकि पिछले वर्ष जब मैं सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आई थी तो अपने कार्यकर्ताओं को विपरीत विचारधारा वालों लोगों से पिटते देखा था। महज एक वर्ष के भीतर लोगों को परिषद कार्यकर्ताओं के सम्मान करते देखना सुखद है। कार्यालय उदघाटन इस पुनीत अवसर पर उस मकान मालिक को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने विपरीत विचारधारा वालों के द्वारा लगातार परिषद कार्यालय को खाली करने के दबाव होने के बावजूद नहीं झूके और कहा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र एवं समाज निर्माण के लिए दिन रात काम करने वाले लोग हैं।

महामंत्री त्रिपाठी ने कहा कि बंगाल बलिदान की धरती है । बंग भंग का आंदोलन हो या स्वतंत्रता संग्राम, हर मौके पर बंगाल ने राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। अपनी मातृभाषा के लिए हमारे कार्यकार्ता राजेश और तापस ने अपने प्राण गंवा दिए। यहां कि मिट्टी राजेश और तापश जैसे कार्यकर्ताओं के रक्त से सनी हुई है। बंगाल में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। उदघाटन के दौरान मंच पर अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के.एन. रघुनंदन एवं प्रांत के पदाधिकारी भी मौजूद थें। ■

पुलवामा के बलिदानी वीरों की याद में तिरंगा रैली

14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने समस्त देशवासियों को झकझोर कर रख दिया था। यह उरी में हुए आतंकी हमले से भी बड़ा था। हमले में 40 जवान बलिदान हो गये। हमला जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर किया गया था। इस काफिले में 2500 जवान शामिल थे। पुलवामा आंतकी हमले के दूसरी बरसी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर बलिदानियों को याद किया।

जम्मू में अभाविप के कार्यकर्ताओं द्वारा सौ मीटर लंबी तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए अभाविप द्वारा पुलवामा में बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिसमें जमकर देश के जयकारे लगाए गए।रैली में बड़ी संख्या में जम्मू के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और बलिदानी जवान अमर रहें के नारे लगाए। विद्यार्थियों का कहना था कि जवानों के बलिदान को कभी भूलाया नहीं जा सकता है। परिषद द्वारा प्रेस क्लब से लेकर बलिदान स्तंब तक यह रैली निकाली गई। इस रैली में हर विद्यार्थी हाथ में तिरंगा पकड़कर घर से निकला था। तिंरगा रैली के दौरान शहर में जाम की स्थिति भी बनी रही। पर लोगों ने इस रैली का पूरा सहयोग दिया और हर किसी ने पुलवामा में बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कटरा में नगर इकाई द्वारा मां भारती के सपूतों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था जहां पर कार्यकर्ताओं ने बलिदानी जवानों के चित्र पर पुष्प अर्पित किये। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानियों का देश सदैव ऋणी रहेगा। जिन अमर बलिदानियों ने हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की, वह धन्य हैं। उन्हें जन्म देने वाली माताएं भी धन्य हैं। हमीरपुर(हि.प्र.) में परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक गांधी चौक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किये। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने वीर सीआरपीएफ जवानों के बलिदान को याद किया। इस मौके पर भारत माता की जय के नारों से पूरा गांधी चौक गूंज उठा।

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में अभाविप कार्यकर्ताओं ने पुलवामा में वीरगति प्राप्त हुए जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने कहा देश की रक्षा के लिए अमर जवानों की बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सैनिकों के साहस से ही देश सुरक्षित है। मधुबनी(बिहार) में अभाविप कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमलों में शहीद जवानों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल लक्ष्मीपुर चौक पर किया गया था। इस सभा में दो मिनट का मौन रखा गया। पुलवामा हमले में शहीद 40 जवानों के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत के सैनिकों के बलिदान को हम सभी अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि सेना का सदैव सम्मान करें तथा उनके बलिदान को हमेशा याद रखें। ■

ABVP submits a letter of suggestion to the Union Minister on the proposed National Science Technology and Innovation Policy (STIP- 2020)

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad submitted a letter of suggestion to the Union Science and Technology Minister Dr.Harshvardhan on the proposed National Science and Technology Policy (STIP) after wide deliberation among the student community, adressing the issues faced by students related to the field of science technology and innovation.

The letter contains suggestions on the availability of research infrastructure to the research scholars of various educational and research institutions, increased clarity on the copyright related issues of research papers by scholars/ scientists, banning journals publishing papers below the expected standards, publication of high quality research work by Indian scientists and scholars and increasing the effectiveness of such work.

In addition to these, suggestions have been shared on increasing the budgetary allocation on developing the research infrastructure, mandatory development of research and innovation culture in the field of primary and secondary education, encouragement to the students with interest in research work from the early days of their career, cooperation between research and technology institutions, development of high quality international standard research institutions at universities and provision for knowledge transfer between research institutes.

Suggestions have also been made by ABVP to the honourable union minister to initiate purposeful contact between industrial and academic sector and developing research programs, establishment of 50 National Technology and Research Institutions for students, teachers and research scholars, increase the amount of fellowships and their beneficiaries, prevention of plagiarism through a single monitoring window, enhance interdisciplinary research compulsorily, increase of eco friendly research in the field of energy, ensure the participation of students of all classes and regions in the field of research, effort to disseminate information on new discoveries, cooperation with other countries in the field of research, increase transparency in appointments.

Nidhi Tripathi, National General Secretary, ABVP, said, "Important steps are being taken to develop and foster a culture of research and innovation in the country. The process of national reconstruction can be expedited through stronger cooperation between the society and science. ABVP has constantly put forth suggestions through various mediums to the central and various state governments to promote research and innovation in the field of education. ABVP hopes that the suggestions shared with the government after wide ranging dialogue on the proposed STIP will be applied in the policy to come. ■

अवध : चौरी-चौरा शताब्दी वर्ष पर अभाविप ने आयोजित किए कई कार्यक्रम

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, अवध प्रान्त के द्वारा चौरी चौरा क्रान्ति के शताब्दी वर्ष को समारोहपूर्वक प्रान्तभर में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठी, रक्तदान एवं दीपांजली के द्वारा इस ऐतिहासिक दिवस को याद किया गया। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर अभाविप लखनऊ महानगर के मेडिविजन आयाम के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह संपर्क प्रमुख डा. राकेश द्विवेदी, महानगर अध्यक्ष डा. मंजुला उपाध्याय, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अपर्णा मिश्रा, महानगर मेडिविजन आयाम सह संयोजक गरिमा सिंह, विभाग संगठन मंत्री अंशुल श्रीवास्तव ने मां सरस्वती व विवेकानंद के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया।

महानगर मेडिविजन सह संयोजक गरिमा सिंह ने बताया कि समाज में एक जागरुक छात्र संगठन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि समाज की आवश्यकताओं में अपना सहयोग दें। इसी क्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है ताकि जरुरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। शिविर में 46 विद्यार्थी व शिक्षकों के द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर में प्रान्त संगठन मंत्री घनश्याम शाही, सत्यम मिश्र आदि ने भी रक्तदान किया।

अभाविप अम्बेडकरनगर की टांडा नगर इकाई के द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रान्त मंत्री अंकित शुक्ल ने संगोष्ठी में छात्रों को संबोधित करते हुए चौरी चौरा की इस घटना को कांड कहना इसकी ऐतिहासिकता को कम करने जैसा है। थाने में लगी आग मामूली आग नहीं थी अपितु यह प्रत्येक भारतीय के हृदय में धधक रही ज्वाला थी जिसका एक रूप उस दिन ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष प्रकट हुआ।

अभाविप लखनऊ जिले में पूर्व संध्या पर काकोरी मेमोरियल पार्क में दीपांजलि का आयोजन कर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। श्रद्धांजलि सभा में केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य शाम्भवी तोमर ने कार्यकर्ताओं के समक्ष इस घटना पर प्रकाश डाला। अभाविप सीतापुर की नैमिष नगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व संध्या के अवसर पर गोमती नदी में 500 दीप प्रवाहित कर बलिदान को स्मरण किया गया। इसी तरह शताब्दी वर्ष के अवसर पर लखीमपुर जिले में दो स्थानों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अभाविप बहराइच के कार्यकर्ताओं ने किसान डिग्री कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया। ■

चौरी-चौरा में मालवीय एक अध्ययन

| डॉ. बालमुकुन्द पाण्डेय |

इस बात पर विचार करना सचमुच महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चौरी-चौरा घटना का स्थाय क्या है ? क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि इतिहास में अमिट छाप छोड़ दे ? घटना क्या है, बस इतनी कि एक भीड़ नें एक पुलिस थाने को घेर कर उसे जला दिया और जिसके भीतर कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गये। वास्तव में यह कृत्य न असहयोग आंदोलन के उन नियमों और शर्तों के अनुकूल था, जो प्रारंभ में गांधी ने अनिवार्य की थीं, न ही भारतीय संस्कृति संवेदनशील परंपरा के अनुकूल। फिर, भी कैसे यह घटना आमजन की सामूहिक चेतना में गहरी छाप छोड़ गई ?

4 फरवरी 1922 की शाम के लगभग 4 ही बज रहे होंगे चौरी-चौरा थाने को दो हजार लोगों की भीड़ घिरे हुए थी। थोड़ी ही देर में थाना धू-धू कर जल उठा। अंदर अनेक पुलिसकर्मी थे। सब के सब भारतीय। कोई अंग्रेज नहीं। इस घटना के बाद गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। झड़प की सूचना देशभर से आ रही थी। इसलिए यह सोचना वाजिब है कि आखिर चौरी-चौरा में ऐसा क्या खास हुआ कि गांधीजी को पूरा का पूरा आंदोलन वापस लेना पड़ा।

आंदोलन के दौरान कार्यकर्ता गांव और बाजारों में पिकटिंग करते, मांस, मछली, मदीरा और विदेश शस्त्रों की बिक्री का विरोध करते थे। जाहिर है इस विरोध में उस वर्ग में नाराजगी बढ़ी, जिनको इस कारण आर्थिक नुकसान सहना पड़ता। चौरीचौरा में भी जमींदार संतबक्श सिंह इन सब विरोधों से खफा थे। मुंडेरा बाजार, जिसका संचालन वह करते थे वहां भी इसका असर पड़ रहा था। 1 फरवरी के दिन एक सरकारी पेंशनर भगवान अहीर और उसके दो साथी मुंडेरा बाजार आए थे। वह संतबक्श सिंह के कारिंदों की शिनाख्त पर पकड़ कर चौरी-चौरा थाने के थानेदार गुप्तेश्वर सिंह के पास ले आ लाए गए। उन्हें खूब पीटा गया और पीट कर छोड़ दिया गया। असहयोगी साथी कार्यकर्ताओं को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने समूह में जाकर थानेदार गुप्तेश्वर सिंह से इस घटना का कारण जानने का निर्णय लिया। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई। 4 फरवरी की सुबह से आसपास की जगहों से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। तीन से चार हजार लोगों की भीड़ इकट्ठे थाने की ओर बढ़ चली। चलने से पहले जो भाषण हुए उससे लगता है कि पुलिस में जमींदार की तरफ के भी लोग थे, जो इस बैठक के आक्रोश को ठंडा करने का प्रयास कर रहे थे। जो आक्रोशित भी थे वह भी बस इतना चाहते थे कि पुलिस आगे कार्यकर्ताओं से बेवजह जबर्दस्ती करने से बाज आए। गुप्तेश्वर सिंह थाने के द्वार पर ही खड़ा था। उसने हाथ उठाकर भीड़ को चेतावनी दी कि वह सभा को गैरकानूनी घोषित कर देगा। इस अव्यवस्था के बीच कुछ लोगों को लगा कि थानेदार ने माफी मांग ली है और वह लौटने लगी। दूसरी तरफ थानेदार ने कुछ चौकीदार इकट्ठा किए थे। उसके संकेत पर वे पीतल की मूर्ति वाली लड़कियों को रगड़ने लगे। माहौल गरमा गया। भीड़ थाने की तरफ बढ़ने लगी। रेलवे लाइन के किनारे खड़े लोगों की तरफ से थाने की ओर रेल लाइन के किनारे पड़ी बजरी की बौछार आई। थाने की ओर से गोली चलने लगी। भीड़ ने थाने को घेर लिया और आग लगा दी।

11 फरवरी को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक थी। प्राप्त अभिलेख के साक्ष्यों से यह निश्चित लगता है कि चौरी-चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन की रीति नीति पर गांधी और मालवीय जी की चर्चा निश्चित रूप से हुई। एक हवा यह भी उड़ी कि गांधीजी का आंदोलन वापसी का निर्णय उनका अपना ना होकर मालवीय जी का था। यह सही है कि गांधी और मालवीय ने कभी खुलासा नहीं किया कि 9 फरवरी 1922 को उनके बीच क्या बातचीत हुई। किंतु चौरी-चोरा के बाद गांधी की सक्रियता का विश्लेषण करने पर इस बात को समझा जा सकता है कि गांधीजी 8 फरवरी तक, जब वे मुंबई के

लिए चले थे, आंदोलन को रोकने का मन बना चुके थे।

बहरहाल, इसी बीच चौरी-चौरा मुकदमा सेशन कोर्ट में शुरू हुआ। जज एच.ई. होल्म्स ने 9 फरवरी 1923 को, 430 पृष्ठों में फैला अपना निर्णय सुनाया। 225 अभियुक्तों में से 172 अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई। एक ही मुकदमे में 172 लोगों की फांसी की सजा अपने आप में अभूतपूर्व और जन चेतना को झकझोर ने वाली था। उस पर अभियुक्तों को अपील करने के लिए केवल 7 दिन का समय दिया गया। मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा। जिला कांग्रेस कमेटी, गोरखपुर ने अपील के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय से सहायता मांगी। पंडित मालवीय वकालत के पेशे से लगभग 20 वर्ष से दूर थे। किंतु आज परिस्थिति दूसरी थी। मालवीय जी ने सदैव अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं उसे राष्ट्रीय कार्य को ऊपर रखा। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और अपीलकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखने को तैयार हो गए। 7 मार्च 1923 को मुख्य न्यायाधीश सर मीयर्स और और न्यायाधीश पिगेट के सामने चौरी-चौरा के मुकदमे की अपील की सुनवाई आरंभ हुई। मालवीय जी ने शुरुआत से ही मुकदमे के मूलभूत वजह को पकड़ कर अपनी बात कहना प्रारंभ किया। उन्होंने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि क्या चौरी-चौरा में कोई राजनीतिक षड्यंत्र हुआ ? मालवीय जी ने अदालत के इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा कि मुकदमे में अभियुक्तों की संख्या कितनी बड़ी है। आरंभ में 232 लोगों के चालान किए गए थे किंतु न्यायाधीश ने केवल 228 का ही मुकदमा सेशन्स को सुपुर्द किया। इनमें से दो मर गए थे और एक का मुकदमा सरकार ने उठा लिया था। सेशन्स जज ने एक साथ 225 लोगों के मुकदमे का फैसला किया। 225 लोगों में से 174 को सजा दी गई। 2 को तो सिर्फ 2 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। बाकी 172 को फांसी की सजा दी गई। मालवीय जी ने इतने अभियुक्तों को एक ही साथ एक ही मुकदमे में फैसला देने के सेशन जज के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।

उन्होंने तर्क रखते हुए कहा कि यह ठीक है कि एक मुकदमे में एक मामले पर तर्क एक हो, किंतु अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि डुमरी की सभा से लेकर चौरी-चौरा की दुर्घटना तक जो घटना घटी क्या उन सब का एक ही कार्यवाही में समावेश किया जा सकता है। दूसरे दिन 8 मार्च को मालवीय जी ने फिर बहस शुरू की। अपनी दलीलें पेश करते हुए उन्होंने उन गवाहों के बयान पढ़कर सुनाएं जिन्होंने अपनी गवाही में डुमरी का वर्णन किया था। मालवीय जी ने कहा कि सरकारी गवाह ठाकुर को छोड़कर और किसी गवाह ने यह नहीं कहा था कि वहां दरोगा को पीटने का निर्णय किया गया था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार की ओर से जो लिखित सबूत पेश हुआ है उससे यह साबित होता है कि सभा में एकत्रित लोगों का उद्देश्य थाने की ओर जाना नहीं बल्कि मुंडेरा बाजार में, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर और शराब की दुकान पर धरना देने के लिए जाना था।

मालवीय जी ने अपने तर्क को और मजबूत किया अभियुक्तों पर लगाये गये धारा पर चर्चा करते हुए कहा कि इन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए 136 (क) धारा के अनुसार प्रांतीय सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है और यदि आज्ञा न ली जाए तो सारी कार्यवाही गैरकानूनी हो जाती है। इसके बाद मालवीय जी ने झुंड के उद्देश्य पर बहस की। तीसरे दिन मालवीय जी ने पुनः गवाहों की गवाहियों को पढ़ा और खासकर शिकारी की गवाही में आई झूठी बातों को अदालत के सामने उखाड़ कर रख दिया। ठाकुर की गवाही में भी अनेक ऐसी बातों को उठाया जो एक दूसरे के विपरीत थी। इस बीच मुख्य न्यायाधीश ने अपनी तरफ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जिनका उत्तर मालवीय जी ने तर्कपूर्ण ढंग से दिया। इसके पश्चात मुकदमा चलता रहा। अभियुक्तों की ओर से के.एन. मालवीय, गोकुलदास, एन.के. सान्याल, डी.एन. मालवीय, के. सी. श्रीवास्तव और ए.पी. दूबे वकील रहे। पूरा मुकदमा उसी राह पर चला जो मालवीय जी ने प्रारंभ में ही दिखा दिया था। परिणाम यह हुआ कि फांसी की सजा पाए 172 अभियुक्तों (इनमें से दो की मृत्यु कारागार में हो गई थी इसलिए वस्तुतः 170) में से 38 अभियुक्त दोषमुक्त हो गए। तीन अभियुक्तों को दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास, 14 को अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 19 को अभियुक्तों को 8 साल कारावास, 27 अभियुक्तों को 5 साल कारावास, 20 अभियुक्तों को 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि 172 लोगों में केवल 19 लोगों को ही फांसी की सजा बची रही। मालवीय जी के अथक प्रयासों से बाकी सभी का जीवन बच सका। ■

समाज के हर वर्ग के उत्थान में योगदान दे रहे हैं परिषद कार्यकर्ता : होसबाले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो राष्ट्र मंदिर है। वैसे ही परिषद के कार्यालय समाज देवता का कार्यालय है। कार्यालय में हर कार्यकर्ता को आत्मीयता मिले, ये प्रयास हमेशा रहे। परिषद के कार्यकर्ता समाज के हर वर्ग से हैं और समाज के हर वर्ग के उत्थान में अपना योगदान दे रहे हैं। परिषद का कार्यालय भवन व्यक्तित्व विकास का स्थल होता है। यह कार्यालय भी अगली पीढ़ी के व्यक्तित्व विकास में अपना योगदान करेगा। हर कार्यकर्ता एक आदर्श बने। पूर्व कार्यकर्ता विकास का जो रथ आगे खींच लाए हैं, उसे नई पीढ़े कार्यकर्ता और आगे ले जाएं। उन्होंने ये बात 12 जनवरी को उज्जैन के ऋषि नगर में नवनिर्मित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय लोकार्पण समारोह के दौरान अपने संबोधन में कही।

परिषद का यह नवनिर्मित कार्यालय राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा: शिवराज

लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह भवन राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। हर जिला और संभाग स्तर पर भी इसी तरह के कार्यालय बनेंगे तो राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का और अधिक योगदान हो सकेगा। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज वे जो भी अच्छे काम कर पा रहे हैं वह विद्यार्थी परिषद में रहकर ही सीखा है। महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रदेश में एक अभियान छेड़ा गया है। यह विचार भी परिषद की ही देन है। मुख्यमंत्री चौहान ने विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता के रूप में उनके अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत पहले यह निश्चय कर लिया था कि उन्हें बतौर अभाविप कार्यकर्ता काम करना है। उन्होंने कहा कि आज उज्जैन में हमने इसका भव्य कार्यालय देखा है। जिस समय मैं परिषद से जुड़ा था,

उस समय भोपाल के लोहा बाजार में परिषद का छोटा-सा कार्यालय हुआ करता था, जिसका किराया 90 रुपये हुआ करता था। कार्यकर्ता के रूप में हम उस कार्यालय में पानी भरकर ले जाया करते थे और सारे काम खुद ही किया करते थे। उस समय सिर्फ आवागमन के लिये एक साईकिल हुआ करती थी। उन्होंने परिषद के प्रमुख रहे सालीगरामजी के काम करवाने के तरीके को रेखांकित किया और कहा कि यह कार्यालय भी पूर्व की भांति समाज को जोड़ने और राष्ट्र निर्माण का कार्य करेगा।

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि वे आज जिस मुकाम पर हैं वह विद्यार्थी परिषद की ही देन है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने भी परिषद में अपने अनुभवों को साझा करते हुए उस दौरान विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के परिषद के सदस्यों के जज्बे के बारे में भी बताया।

कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि यह भवन नेतृत्व के गुण का विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभायेगा। उन्होंने भी सालीगरामजी के साथ किये गये अपने कार्य के अनुभव को साझा किया।

इस अवसर पर अतिथियों ने पुस्तकालय एवं वाचनालय का भी फीता काटकर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण में योगदान देने वाले शिल्पकारों को मंच पर बुलाकर शाल, प्रतीक चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। ■

Initiate action against college management, reduce fee by 50 % : ABVP

The activist of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) on 10 th February staged a protest corporate college for violating board norms and forcing student to pay the entire fee. They demanded that the Telangana State Board of Intermediate Education (TSBIE) issues guidelines directing colleges to college to collect only 50 % of the total tuition fee for the academic year 2020-21.

"Parents are not position to clear the entire fee in three to four months. Moreover, when a student had not used any facilities in the campus and is attending physical classes only for three months, why should he/she pay the entire fee," questioned P. Srihari, general secretary, Hyderabad ABVP adding that about 100 of them participated in the protest and 40 were picked up by the police. He said that college have no right to demand full fees as they are hardly paying 10 % of their staff to run classes and are saving on their bills.

The ABVP activist also alleged that many colleges are also collecting full hostel fees even students have spent a major part of the academic year at their homes. They demanded that the inter board initiates action against erring junior colleges and lodges a criminal case against them. They also said that the board should inspect colleges and shutdown those running without required permission. ■

विद्यार्थी-युवाओं के सुझावों को लेकर राष्ट्रीय मत्स्य नीति पर भेजा ज्ञापन

अभाविप ने राष्ट्रीय मत्स्य नीति के प्रारूप में सुझाव के सम्बंध में मतस्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को अपना ज्ञापन प्रेक्षित किया। अभाविप ने मत्स्य मंत्रालय के इस नीति अभिनंदन करते हुए कहा कि इस नीति के लागू होने से सिर्फ रोजगार में वृद्धि ही नहीं बल्कि जलीय कृषक तथा मछुआरों की आय भी दोगुनी होगी, जिससे भारत मत्स्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

अभाविप ने अपने ज्ञापन में मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों तथा जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी विकास हो, राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री मत्स्य विभाग की देखभाल के लिये एक सुचारू तंत्र की स्थापना हो, हर राज्य में जलीय कृषि तकनीकी वाले मैदान की स्थापना, जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान खोलने, जलीय कृषक को स्टार्ट-अप के लिए बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के लोन, मत्स्य विभाग को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में मत्स्य शोध संस्थान खोलने आदि सुझावों को मांगपत्र में सम्मिलित किया हैं।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्रीनिधि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की इस नीति से जलीय कृषक तथा मछुआरों के आय में वृद्धि होगी तथा इस क्षेत्र में शिक्षा और शोध का मज़बूत ढाँचा खड़ा करने से विद्यार्थी और शोधार्थी के लिये नये अवसर पैदा होंगे। कैम्पस और इंडस्ट्री को जोड़ने से रोजगार के नए अवसर आये, जिससे भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की और अग्रसर होगा। आशा है सरकार अभाविप के सुझावों पर विचार करेगी तथा इन्हें राष्ट्रीय मत्स्य नीति में सम्मिलित करेंगे। ■

Educational institutions should be opened without delay, one year should be extended for research scholars: ABVP

ABVP delegation met with the Education Minister and submitted memorandum to resolve the current issues of the academia.

A delegation comprising of National General Secretary and National secretaries of the AkhilBharatiyaVidyarthiParishad met Union Education Minister Ramesh Pokhriyal 'Nishank' and submitted a memorandum to solve the current problems of the academic world.

The delegation proposed education minister to open all higher education institutions in the traditional (offline) mode for the students at the earliest, and put before him suggestions to solve the problems caused in the education world due to the corona pandemic.

In view of the loss and delay in research work during the Corona pandemic, ABVP requested to provide an additional time of one year to research students and provide research funds for that period as well as to provide all types of scholarships to students at the earliest.

ABVP emphasized over the need to make full arrangements for imparting training to teachers at the college level to increase the use of technology, to make online arrangements in schools, colleges and universities in emergency and to develop online libraries to ensure availability of relevant reading material to the students.

Underlining the need to provide relief to the students who are not able to access the educational institutions and parents facing economic crisis due to Corona epidemic, ABVP demanded Hon'ble Minister of Education to provide them a fee waiver. In view of the worrying situation of the state universities, the ABVP delegation emphasized upon the need for appointment of regular teachers, proper and consistent funding and increasing the amount of funds allocated to UGG and RUSA and its proper and inclusive classification.

ABVP's National General Secretary NidhiTripathi said, "The ABVP has been continuously giving suggestions for the expedient implementation of the National Education Policy. In light of this, today, we met the Hon'ble Union Minister of Education and discussed the same. We hope that the Government will take appropriate steps on our demand and students can return to their campuses very soon and continue their studies as earlier. "

अध्ययन दल की रिपोर्ट में खुलासा, किसान आंदोलन पर वामपंथियों का कब्जा

नये कृषि कानून के खिलाफ 19 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन की पटकथा पर हरियाणा के विद्यार्थियों के अध्ययन दल की रिपोर्ट में खुलासा किया है कि किसान आंदोलन पर वामपंथियों का कब्जा हो चुका है। भिवानी अध्ययन दल के प्रमुख राहुल शर्मा ने कहा कि 8-12 जनवरी तक हमलोग झड़ौदा बॉर्डर से कुछ दूरी पर रूके थे। हमलोगों ने देखा कि आंदोलन में पंजाब के मजदूर वर्गी, बुजूर्ग, व एसएफआई, एआईएसए, सीपीआई, सीपीएमआई, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान मोर्चा, हरियाणा-पंजाब भाईचारा ग्रुप इत्यादि की सक्रिय भूमिका है। आंदोलनकारियों से बातचीत करने से पता चला कि आंदोलन में सिर्फ भाजपा और संघ विरोधी बातें कही जाती है। जब इनसे कृषि कानून के बारे में पूछा तो नहीं बता पाये, सिर्फ काले कानून को वापस करने की रट लगाते रहे। दूसरे अध्ययन दल का नेतृत्व कर रहे राहुल गोयत बताते हैं कि हमलोग टिकरी बॉर्डर पर गये थे, प्रथम दृष्टया यह पंजाब का आंदोलन प्रतीत होता है लेकिन अब धीरे - धीरे हरियाणा के लोग भी पहुंच रहे हैं। कहने को तो यह गैर राजनीतिक आंदोलन है लेकिन लगभग सभी विपक्षी पार्टियों की मौजूदगी बढ़ -चढ़कर है, ये अलग बात है कि झंडा केवल किसान यूनियन और वामपंथी संगठनों के लगे हैं। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन की खास बात यह है कि यहां लोगों की संख्या कम लेकिन आसियाने ज्यादा है।

सिंघु बॉडर पर गये विद्यार्थियों की मानें तो वहां पर खाने - पीने, रोजाना जरूरत की सामानों के साथ - साथ अन्य सभी सुख-सुविधायें मौजूद हैं। निरवैर सिंह बताते हैं कि ईपीई से ही किसानों का जमावड़ा दिखाई दे रहा था, ट्रेक्टर की टोली को ही लोग अपना घर बना लिये हैं। टिकरी बार्डर की कहानी को विस्तार से बताते हुए दिनेश शास्त्री कहते हैं कि हमलोगों का छः बार टिकरी बार्डर पर जाना हुआ लेकिन वहां एक भी पर्चा नहीं दिखा जिसमें तीनों कृषि कानून का विश्लेषण या खामी लिखा हो। अधिकांश लोगों को ये भी नहीं पता कि कृषि कानून क्या है? पूछने

पर बताते हैं कि यह काला कानून है इसके तहत हमारी जमीनें छिन कर कंपनियों को दे दी जाएगी। यहां की व्यवस्था और उसके फंडिग की पड़ताल करते हुए हमलोग एक टेंट में पहुंचे। टेंट के बाहर कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्पेन, अमेरिका और फ्रांस के ध्वज लगे थे। वहां की व्यवस्था देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। टेंट में जीम के मंहगे - मंहगे साजोसमान रखे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे युवाओं से जब इसके बारे में पूछा तो उनका कहना था हमारे भाई विदेश में रहते हैं। ये सब देखकर लगा कि सही में इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही है, हांलाकि इस तरह की सुविधा अन्य टेंट में नहीं दिखी। सूचना तंत्र व्यवस्था को देखकर लग रहा था मानों ये आंदोलन नहीं इंवेंट है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सूचनाओं का प्रसारित किया जा रहा था। सन्नी नारा कहते हैं भाजपा नेताओं के वीडियो को एडिट कर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। सुमित मेहता कि मानें तो इस आंदोलन को वामपंथियों ने हाईजेक कर लिया है, वे इस आंदोलन के जरिये अपने प्रोपगेंडा चला रहे हैं। छात्राओं के द्वारा वामपंथी विचारधारा के साहित्य को बंटवाया जा रहा है, जब हमने इन छात्राओं से बात की तो बताया कि लगभग एक हजार छात्रा इस कार्य में लगी हुई हैं। जगह - जगह पर सिख और मुस्लिम धर्म के प्रतीक चिह्न लगे हुए हैं जबकि हिंदू प्रतीक खोजने पर भी नहीं मिलता। आगे सुमित बताते हैं कि कई स्थानों पर हमें भिंडारावला के पोस्टर लगे हुए है, इसके साथ ही देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को छुड़ाने के लिए नारे भी लिखे गये हैं। ■

आखिर उजागर हो ही गया किसान नेताओं का असली चेहरा

| मनोज कुमार मिश्र |

यह शुरू से ही लग रहा था कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने पर सरकारी वकील ने सुरक्षा के खूफिया सूत्रों के हवाले जानकारी दी थी कि आंदोलन में देश विरोधी नक्सल संगठन और खालिस्तान से जुड़े आतंकवादी घूसपैठ कर गए हैं। तब इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में आतंक का नंगा नाच किया गया। देश की आन-बान-शान लालकिला पर योजनाबद्ध तरीके से हजारों की तादात में हमला करके तोड़-फोड़ करते हुए सुरक्षा बलों को पीटा गया और धार्मिक झंडा फहराया गया। इस उपद्रव में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने गजब संयम का परिचय दिया। तलवार, भाला, लाठी-डंडे और दूसरे हथियार लिए इन हुड़दंगियों की मार खाकर उन्हें हुड़दंग करने से रोकते रहे जिसमें करीब चार सौ पुलिसवाले घायल हुए, अनेक गंभीर हालत में पहुंचा दिए गए थे। इस भीड़ की अगुवाई पंजाब का घोषित आतंकवादी लखवीर सिंह उर्फ लाखा सिघाना और पंजाबी अभिनेता दीप सिंद्धू आदि कर रहे थे।

दिल्ली की पांच सीमाओं पर ट्रेक्टर परेड की लिखित इजाजत दिल्ली पुलिस से लेने के बाद तथाकथित किसान नेताओं ने भीड़ को समय से पहले उत्तेजित करके दिल्ली के भीतर जाने के लिए उकसाया और हिंसा करवाई। इसी के चलते जो दिल्ली में कभी नहीं हुआ था वह इस किसान आंदोलन के नाम पर किया गया। अपनी साख बचाने के लिए किसान नेता आंदोलन को जारी रखने के अभियान में जुटे हुए हैं। लाल किला की घटना ने दिल्ली और देश भर के लोगों को उद्वेलित कर दिया है। किसान आंदोलन संसद के सितंबर 2020 के बनाए तीन कृषि कानूनों को खत्म करवाने के लिए शुरू किया गया था। इन तीन कृषि कानूनों में एक कानून मंडियों के बाहर भी उपज बेचने की इजाजत देने से है। दूसरा कानून किसानों को सहकारी खेती की अनुमति देने वाला है और तीसरे में अनिवार्य फसलों पर से रोक हटाने का है (1.कृषक उपज व्यापार

और वाणिज्य(संवर्धन व सरकीकरण) कानून-2020,2. कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कानून-2020 और 3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून-2020)। सरकार यह समझाती रही कि इन बिलों से किसानों को केवल लाभ ही होगा। उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता और मंडियां खत्म नहीं की जा रही है। फसलों को खुले में बेचने की इजाजत दी जा रही है। देश में मंडी और उसमें सक्रिय आढ़तियों की व्यवस्था पंजाब और हरियाणा में ही सबसे मजबूत है। पंजाब से ही कुछ किसानों का जत्था दिल्ली की एक सीमा सिंधू बार्डर पर 26 नवंबर से इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन शुरू किया। उनके साथ हरियाणा के किसान भी जुड़े। एक और सीमा टिकरी बार्डर पर आंदोलन चलने लगा। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत गाजीपुर पर और उसी यूनियन का एक धड़ा चिल्ला बार्डर पर धरना देने लगा। इन धरनों में चालीस से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं उसमें वाम पंथी दलों के कई संगठन घोषित रूप से शामिल हैं।

किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी और समाधान के लिए चार सदस्यों- भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत की समिति बना दी। किसान संगठनों ने इस समिति के सदस्यों को बिल का समर्थक मान करक बात करने से इंकार कर दिया। बातचीत शुरू होने से पहले ही एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने समिति से इस्तीफा दे दिया। किसान नेता फिर से सरकार से ही बात करने को तैयार हो गए थे। 11 वें दौर की बातचीत में सरकार ने बिलों को लागू करना साल-डेढ़ साल टालने का प्रस्ताव दिया लेकिन किसान संगठन बिल वापसी से कम पर तैयार नहीं थे। इसी के साथ नए सिरे से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानून बनाने की मांग भी जोड़ दी गई। सरकार ने फिर अगले दौर की बातचीत के लिए प्रस्ताव नहीं दिया। उसके बाद किसान संगठनों के नेता 26 जनवरी को गणतंत्र दिन दिल्ली के महात्मा गांधी मार्ग(रिंग रोड) पर ट्रेक्टर परेड करने की जिद पकड़ी। पुलिस ने दिल्ली की सीमा पर पांच रास्ते तय किए। यह भी तय किया गया कि राजपथ पर परेड समाप्त होने पर दोपहर बाद किसान परेड होगी। किसान नेताओं ने लिखित में पुलिस को भरोसा देकर शांति बनाए रखने और तय बातों पर अमल करने का भरोसा दिया। राजपाथ पर परेड शुरू होने से ही पहले सिंधू बार्डर, टिकरी बार्डर और गाजीपुर बार्डर से किसान पुलिस बैरियरों को तोड़ते हुए दिल्ली के भीतरी हिस्सों में घूसे। सुरक्षा बलों पर लाठा-डंडे और घातक हथियारों से हमला करते हुए नांगलोई, आईटीओ, अक्षरधाम के बाद ऐतिहासिक लाल किला पर पहुंच गए। हर जगह खूब उत्पात मचाया। पुलिस वालों को जान बचानी भारी पड़ रही थी। उन्होंने गजब संयम का प्रदर्शन किया। लाल किला पर खूब तोड़फोड़ करके उस स्थान पर धार्मिक झंडा लगा दिया जहां 1947 से हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। बाद में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करके धार्मिक झंडे को हटाया गया और पुलिस ने दंगाईयों के खिलाफ कारवाई शुरू की।

26 जनवरी को लाल किला समेत दिल्ली के अनेक इलाकों में हुए दंगे के बाद किसान आंदोलन खत्म सा होने लगा। स्थानीय लोग किसानों के धरने से पहले भी परेशान थे लेकिन तब कुछ लोगों की उनके प्रति सहानुभूति भी थी। बाद में तो सभी सीमाओं से धरना हटवाने के लिए स्थानीय लोग प्रदर्शन करने लगे। कई संगठन को हंगामें के बाद आंदोलन समाप्त करके वापस लौट गए। गाजीपुर सीमा पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत किसानों के तंबू उखड़ता देख परेशान हो गए। सरकार ने भी सहुलियतें वापस ले ली। धरना हटाने के लिए बड़ी तादात में सुरक्षा बल तैनात करा दिया। धारा 144 लागू कर दी गई। आंदोलन समाप्त करने की जिद ठाने बैठे राकेश टिकैत ने आंसुओं का सहारा लेकर फिर से आंदोलन को जारी रखवा लिया है। भाजपा के विरोधी दलों के लिए राकेश टिकैत मुद्दा बन गए। राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई चौधरी अजित सिंह की लोक दल से लेकर पहले दिल्ली में इन तीन कृषि कानूनों को लागू करके विरोध होने पर रद्द करने का प्रस्ताव करने वाली आम आदमी पार्टी(आप) आदि को भी अपना पैर जमाने का मौका मिल गया है। किसान आंदोलन को तो किसानों तक ही बनाए रखना इन किसान नेताओं के लिए न तो संभव लग रहा है और न ही उनकी नीयत ही दिख रही है। आंदोलन तो चाहे जब तक चले या जैसे चले, वह तो पूरी तरह से देश विरोधी संगठनों के चंगुल में फंस गया है।

अपने रास्ते से भटक चुका है किसान आंदोलन

| अवनीश सिंह 'राजपूत' |

कहते हैं कि नदी जब अपना रास्ता भटक जाती है तो वो विनाश ही लेकर आती है, ठीक उसी तरह किसानों का ये आंदोलन भी अपने रास्ते से भटक चुका है। किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन कतई नहीं रहा है। पिछले ढाई महीनों से आंदोलन के नाम पर जो हजारों लोग सड़क पर तंबू डाल कर बैठे हैं उससे एक बात तो साफ है कि आंदोलनकारियों में किसान कम और राजनीति से प्रेरित लोग ज्यादा हैं। खास कर वह जो अपने को किसान नेता कहलाना पसंद करते हैं। जो मासूम किसान धरने पर बैठे हैं, वे उसी तरह बरगलाए गए लोग हैं जैसे शाहीनबाग में धरना पर बैठे लोग एक तोते की तरह रटे-रटाए दोहे पढ़ रहे थे।

जैसे शाहीनबाग में ज्यादातर आंदोलनकारियों को यह नहीं पता था कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) क्या है? बस उन्हें डरा दिया गया था कि अगर यह कानून वापस नहीं होगा तो सभी गैर हिंदू को देश से निकाल दिया जाएगा। ठीक उसी तरह दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को यह पाठ पढ़ा दिया गया है कि अगर किसान कानून वापस नहीं लिया गया तो उनकी जमीन बड़े उद्योगपतियों को दी जाएगी और वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे।

गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी में जो हिंसा और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां हुईं, उनसे सारा देश उद्वेलित है। कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे किसान आंदोलन ने हिंसक और राष्ट्रविरोधी स्वरूप लेकर गण, तंत्र और गणतंत्र, तीनों को शर्मसार किया। किस तरह देश की ऐतिहासिक धरोहर लाल किले पर कुछ मुट्ठी भर हुड़दंगी एक धर्म विशेष का झंडा फहराते हैं, किस तरह निहंगों की टोली पुलिस को निशाना बनाती है। ये सब किसी से छुपा नहीं है। सब कुछ परत-दर-परत सामने आ रहा है।

दिल्ली की सभी सीमाओं पर जहां किसान आंदोलनकारी बैठे थे 26 जनवरी को सुबह 8 बजे से ही गड़बड़ी के लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। आंदोलनकर्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ती गयी और फिर धक्का-मुक्की के बीच आंदोलनकारी लोग बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ चल पड़े। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश भी की, पर उनकी एक न चली। पहले अक्षरधाम और फिर आईटीओ पर पुलिस और आंदोलनकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी और आंसू गैस का आदान-प्रदान हुआ और बात बिगड़ती चली गयी। कुछ पुलिसवालों को ट्रैक्टरों के नीचे दबाने की कोशिश भी हुई।

इस अराजकता के माहौल में एक आंदोलनकर्ता की मौत हो गई। इसके बाद पूरे दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आंदोलनकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प होती रही। हद तो तब हो गई, जब आंदोलनकर्ताओं ने लाल किले पहुंच कर अपना झंडा उस जगह लगा दिया, जहां देश के प्रधानमंत्री हर साल स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराते हैं। यही नहीं कुछ देर बाद यह झंडा किले के सबसे ऊपरी तल के मध्य गुम्बद पर भी लगा दिखा। ऐसी जगह पर आंदोलनकर्ताओं का पहुंचना और अपने झंडे को वहां स्थापित करना एक सोची समझी कुटिल योजना की तरफ इशारा करती है। यह सीधे-सीधे देश की चुनी हुई सरकार को चुनौती देने सरीखा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कृषि कानूनों के विरोध से शुरू हुआ यह आंदोलन देखते-देखते खालिस्तानियों और अलगाववादियों के हाथ की कठपुतली बन गया। उपद्रव और हिंसा शुरू होने बाद किसान नेतागण जो अब तक न्यूज चैनलों पर बयान देते दिखते थे, पहले तो गायब रहे और जब आए तो इसे सरकार की साजिश या आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश बताते रहे।

इस आंदोलन में शुरू से ही खालिस्तानी कनेक्शन दिखने लगा था। सिंघु बॉर्डर पर आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर और खालिस्तानी झंडे इस बात की गवाही दे रहे थे। इतना ही नहीं किसान आंदोलन के बीच "सिख फॉर जस्टिस" नाम के संगठन की भूमिका भी संदिग्ध पाई गयी। यह संगठन भारत में प्रतिबंधित है। इसका एजेंडा पंजाब में अलग खालिस्तान बनाने का है। इस संगठन ने गणतंत्र दिवस पर लाल किले में खालिस्तानी झंडा फहराने पर लोगों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की थी।

दिल्ली के सीमांत इलाकों में धरने पर बैठकर हठधर्मिता का परिचय दे रहे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों के समर्थन में भारत विरोधी ताकतों का सक्रिय हो जाना चिंताजनक है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के पक्ष में स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जैसे ट्वीट किए, वे भारत के खिलाफ साजिश की ही कहानी कहते हैं। उनके ट्वीट ने साबित किया कि वह भारत विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रही हैं। गायिका रिहाना

के ट्वीट के पीछे भी कनाडा में बैठे खालिस्तानियों का हाथ माना जा रहा है। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में सक्रिय खालिस्तानी कृषि कानून विरोधी आंदोलन को हवा देने के साथ भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। ग्रेटा ने अपने ट्वीट के जरिये जो गूगल टूल किट शेयर की, उसे भी तैयार करने का संदेह कनाडा के खालिस्तानियों पर ही है। यह टूल किट भारत को बदनाम करने और यहां अराजकता फैलाने की साजिश का दस्तावेज ही है। ग्रेटा के गुनाह की पुष्टि इससे होती है कि जब उनकी टूल किट भारत विरोधी एजेंडे से लैस दिखी तो उन्होंने उसे हटा लिया। उनके ऐसा करने के पहले ही भंडाफोड़ हो गया।

यह अच्छा हुआ कि ग्रेटा और रिहाना की हरकत को विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करार देते हुए उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से आगाह किया। अच्छी बात यह भी हुई कि यही काम आम तौर पर राजनीतिक मसलों पर चुप रहने वाले क्रिकेटरों और फिल्मकारों ने भी किया। सबसे दयनीय यह रहा कि कुछ बुद्धिजीवियों के साथ मीडिया वालों का एक धड़ा इन क्रिकेटरों और फिल्मकारों की निंदा करने में जुट गया। ऐसा करके उन्होंने यही जाहिर किया कि वे सरकार और देश के विरोध में अंतर करना भूल गए हैं। ये वही लोग हैं जो किसान नेताओं की तरह यह बताने को तैयार नहीं कि आखिर कृषि कानूनों में खामी क्या है? यही हाल किसान नेताओं को उकसाने में जुटे विपक्षी नेताओं का भी है। उनके पास कृषि मंत्री के इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि कथित काले कानूनों में काला क्या है और उनसे किसानों को नुकसान कैसे होगा?

अपने देश में सामाजिक आंदोलनों की गौरवशाली परंपरा रही है। हाल में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल आंदोलन चलाया, जिसे अपार जनसमर्थन मिला। अन्ना आंदोलन का स्वरूप सुधारात्मक था। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनवाना चाहता था, जबकि किसान आंदोलन का स्वरूप प्रतिरोधात्मक है। यह कानूनों को समाप्त कराना चाहता है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में भीड़ जुटाना कठिन नहीं, लेकिन उसके द्वारा कानून वापस लेने का दबाव डालना एक गलत नजीर है। कल किसी और कानून को वापस लेने की ऐसी ही मांग उठ सकती है। सामाजिक आंदोलनों का लोकतंत्र में सदैव स्वागत है लेकिन उन्हें भारतीय लोकतंत्र को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान आंदोलन ने लोकतंत्र को बंधक ही नहीं बनाया, उसे शर्मसार कर उस पर एक धब्बा भी लगा दिया। ■

Post-pandemic Union Budget geared towards actualising the goal of Aatmanirbhar Bharat: ABVP

The pronouncements made in the Union Budget in respect of introducing systemic changes in the fields of manufacturing, health, education and transport as well as creating new and enabling structures are in sync with the aspirations of the country in the post-pandemic era. Moreover, the apportionment of funds in respect of women, rural development, backward classes, scheduled caste and scheduled tribe related affairs is praiseworthy.

Among other things, pronouncements regarding the effective implementation of the National Education Policy, allocation of rupees 50,000 crores for the National Research Foundation for a period of five years, establishment of new schools, especially 750 schools in tribal areas, constitution of Higher Education Commission of India and the proposed establishment of a Central University in Ladakh are significant for the comprehensive development of education sector. Moreover, the provision of 35,000 crore rupees worth of scholarship for the Scheduled Caste students is significant for promoting inclusive learning across the nation.

NidhiTripathi, National General Secretary, while welcoming the education budget, said, "This budget is seemingly commensurate with the widely felt national aspirations. When compared with the allocation during the preceding financial year, the more than two-fold increase in the health budget is a welcome development, especially in light of the challenges experienced during the Covid-19 pandemic. Investments in infrastructure will generate new job opportunities for the youth. The inclusive and all-encompassing approach adopted in the Union Budget is commendable." ■

देश से बढ़कर कुछ नहीं: निखिल रंजन

गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर अभाविप, झारखंड द्वारा रांची में आयोजित 'राष्ट्र रंग' कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन ने कहा आजाद होने के बाद देश सुरक्षित है तो उसमें वीर जवानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम लोग निश्चिंत होकर रहते हैं क्योंकि हमारे सैनिक सीमाओं की रक्षा में डटे हुए हैं। उन्होंने युवाओं को से कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। युवाओं को हमेशा देश की तरक्की व सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश की आजादी को संभाल कर रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएं।

अभाविप, झारखंड के प्रांत अध्यक्ष प्रो. नाथू गाड़ी ने कहा कि इस देश की सुरक्षा में सैकड़ो माताओं की गोद सूनी हो जाती है, हजारों बहनों बेटियों के मांग का सिंदूर मिट जाती है, तब कहीं जाकर हमारा देश सुरक्षित रहता है। इस देश की सुरक्षा में सर्वस्य न्यौछावर करने वालो को सम्मान देना हमारे लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए अनिकेत अमन ने कहा कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित यह कार्यक्रम सैनिकों को समर्पित था इसलिए इसका नाम 'राष्ट्र रंग' दिया गया। कार्यक्रम में सैनिक सम्मान समारोह में अमर बलिदानी स्व. हवलदार प्रभसहाय तिर्की की छोटी बहन, बलिदानी स्व. अभिषेक कुमार साहू के भाई परमानंद कुमार, सिपाही तारणी यादव को मंच पर सम्मानित किया गया। राष्ट्र रंग में सैनिक सम्मान समारोह के साथ - साथ नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, गीत एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी मात्रा में शहर के छात्र – छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन रांची स्थित शहीद स्मृति सभागार, केन्द्रीय पुस्तकालय मोराबादी में किया गया था। कार्यक्रम की शुरूआत परिषद गीत एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, प्रांत अध्यक्ष नाथू गाड़ी, राष्ट्रीय मंत्री कु. विनीता इंदवार, प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, प्रांत सह मंत्री मोनू, महानगर अध्यक्ष डॉ. आनंद, महामंत्री दुर्गेश आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' फरवरी-मार्च संयुक्तांक 2021 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

पद्म पुरस्कार

विलक्षण प्रतिभाओं को सम्मानित कर गौरवान्वित होता भारतीय समाज

| देवेन्द्र शर्मा |

सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं की उपस्थिति उस समाज के जीवंत, उन्नतिशील होने का प्रमाण है, विलक्षण प्रतिभाओं को सम्मानित कर समाज स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है, साथ ही साथ आदर्शों की स्थापना करता है जो उत्तरोत्तर सामाजिक उन्नति के लिये उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। श्रेष्ठता के मापदण्डों को निरंतर ऊंचाई देना किसी भी सभ्यता संस्कृति के लिये अत्यंत गत्यतमक पक्ष है। सही अर्थों में कहें तो प्रतिभाओं का सम्मान करके समाज स्वयं निरंतरता को स्थायी करता है। स्वतंत्रता के साथ औपनिवेशिक सत्ताधीशों के द्वारा दिये गये पुरस्कारों को समाप्त कर दिया गया था। भारतीयों के लिये पद्म पुरस्कारों की घोषणा 1954 में भारत रत्न के साथ की गयी थी। जिसका लक्ष्य समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिये प्रतिभाओं को सम्मानित करना था। आरंभ में वी.के. कृष्ण मेनन, डा. होमी जहांगीर भाभा, श्रीमति रतन शास्त्री जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मिला वहीं पर बड़ी संख्या में 'सिविल सर्विस' से संबन्धित व्यक्तियों को यह पुरस्कार देने की आलोचना भी होती रही। जैसे 1955 में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने स्वयं को ही भारत रत्न दे दिया। 1962 में पद्मजा नायडु तथा विजय लक्ष्मी पन्डित को पद्म विभूषण देने पर भी प्रश्न उठाये गये। 1964 में अलगाव की आग भड़काने में आगे रहने वाले शेख अब्दुल्ला को पद्म भूषण देनें की स्वयं कांग्रेस में भी प्रतिक्रिया के स्वर सुनायी दिये। ऐसे ही लगभग प्रत्येक वर्ष ईसाई तथा मुस्लिम मजहब के पादरियों तथा मौलानाओं को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मनित किये जाने के औचित्य पर भी प्रश्न उठाये जाते रहे। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा फ़िरोज खान गांधी ने अपने पिता जवाहर लाल नेहरु की भांति स्वयं को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया। इस वर्ष 133 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो एक बड़ी संख्या थी। 1972 में भी यह संख्या 150 के पास पहुंच गयी। यहां हमें यह ध्यान देना चहिये कि इस समय तत्कालीन सरकार के कुशासन के विरुद्ध जनता में असंतोष बढता जा रहा था। इसी समय हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण करने वाले विवादास्पद चित्रकार मक्बूल फ़िदा हुसैन को भी पद्म पुरस्कार दिया गय। आपातकाल में पद्म पुरस्कारों को लेकर जिस प्रकार की बंदर बांट हुई उसके कारण जनता पार्टी की सरकार में यह पुरस्कार दिये ही नहीं गये। 1980 में जब यह पुरस्कार दिये गये तब मदर टेरेसा नाम की ईसाई मत की प्रचारिका को भारत रत्न देने पर फ़िर से संशय उठे, यह स्पष्ट रहे कि उनके संगठन पर हिन्दुओं के धर्म-परिवर्तन के आरोप लगते रहे थे, विदेशी धन के अनाधिकारिक लेन देन तथा बच्चों की तस्करी तथा उन्हें बेचने के आरोप भी लगते रहते थे।

यह पुरस्कार कई प्रकार के वैचारिक राजनैतिक विवादों का केन्द्र भी रहते आये हैं। एक समय ऐसा भी आया कि पद्म पुरस्कार एक दल विशेष विचारधारा के पैरोकारों और उसके हरावल दस्तों के चाटुकारों को दिये जाने लगे। सामान्य जनमानस में यह धारणा व्याप्त हो गयी थी कि दल विशेष से जुड़े ऐसे प्रभावी लोगों को ही पद्म पुरस्कार दिये जायेंगे। अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे यह कहावत कांग्रेस ने चरितार्थ कर दी और पद्म पुरस्कार रेवड़ियों की तरह बांटे जाने लगे। राडिया टेप की कुख्यात पत्रकार बरखा दत्त, सामाजिक वैमनस्य फ़ैलाने के लिये बदनाम पत्रकार राजदीप सरदेसाई, विद्वेषपूर्ण राजनैतिक विश्लेषण करने वाले विनोद दुआ जैसे व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला तब इन पुरस्कारों की गरिमा को ठेस लगी।

पद्म पुरस्कारों की उपादेयता पर बड़ी बहस भी खड़ी हुई, यहां तक की समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने इन पुरस्कारों को समाप्त करने की मांग यह कहते हुये की कि इनसे अब ब्रिटिश राज के समय जो राय बहादुर खान बहादुर सर जैसी उपाधियों की दुर्गन्ध आने लगी है। इधर पद्म पुरस्कारों को लेकर परिवर्तन दिखने लगा है, जिससे निर्णय चयन को लेकर आम जनमानस में संतुष्टि का भाव है। 2015 में वैष्णव सन्त शिरोमणि स्वामी श्रीरामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण मिला स्वतंत्र भारत के इतिहास में परंपरा के स्थापित सन्त को प्रथम बार ऐसा पुरस्कार मिला। ऐसे ही 'स्टेच्यु ओफ़् यूनिटी' के मूर्तिकार श्री राम वन जी सुथार को पद्म पुरस्कार मिलना सुखद रहा। इसी प्रकार श्रीमती सू. बोम्मु गौडा जो

हलाक्की वोकलिंगा समुदाय से आती हैं, उन्हें वनवासी गीतों की परंपरा को संजोये रखने तथा उसे आने वाली पीढी को देने के कार्य के लिये पद्म पुरस्कार दिया गया। यह अपने आप में पद्म पुरस्कारों की चयन तथा निर्णय प्रक्रिया में बड़े बदलाव को रेखांकित करने के लिये पर्याप्त है। इस वर्ष भी मणिपुर के थौबाल जिले के वांगिंजग कस्बे की 88 वर्षीय श्रीमति राधे देवी हन्जबाम ओंग्बी को पद्म पुरस्कार मिलना यह स्पष्ट करता है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वालों का भी सम्मान होना सम्भव है। राधे देवी जी मणिपुरी वधुओं के वैवाहिक परिधान जिसे पोट्लोई कहा जाता है उस परंपरा को सशक्त करने के लिये जानी जाती हैं। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि राधे देवी चाय की दुकान चलाया करती थी। उनकी यह यात्रा अनेक अर्थों में रोमांचकारी है जिसकी परिणति सुखद है।

राजस्थान के श्री श्याम सुन्दर पालिवाल जी सामाजिक वानिकी पर्यावरण तथा बालिका सुरक्षा के लिये जो सामाजिक हस्तक्षेप किया उसे अब पिपलान्त्री माडल कहा जाने लगा है, राजस्थान के मेवाड क्षेत्र में यह माडल मौन क्रान्ति ला रहा है जिसके बहु-आयामी प्रभाव हैं। पालिवाल जी ने अपनी पुत्री को खोने के बाद उसकी स्मृति में गोचर भूमि में 111 पौधे लगाये। यही भाव आंदोलन बन गया जब पालीवाल जी गाँव में जन्मी प्रत्येक बालिका के जन्म पर 111 पौधे लगा कर उनकी देखभाल करने लगे। कन्या के माता-पिता से शपथ पत्र लेना, बिटिया का विवाह समय से पहले न करना, कन्या भ्रूण की जाँच न करवाना आदि सामाजिक नियमों ने मेवाड के राज्समन्द जिले में कायाकल्प करना आरंभ कर दिया है।

मेघालय के पहाड़ियों से घिरे हुये पश्चिम गारो जिले के तिक्रिकिल्ला ब्लाक के गोन्दा जस्मिारे गांव के श्री नन्द्रो माराक ने काली मिर्च की खेती में नवोन्मेगष से काली मिर्च के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसे द्वि-फ़सली बनाकर प्रति एकड़ आय में वृद्धि के माडल के रूप में स्थापित किया है। श्री नन्द्रो माराक जी को 2018 में वियतनाम में हुई काली मिर्च की अंतर्राष्टीय कांफ्रेंस में भी सम्मानित किया गया था। यह तीन उदाहरण केन्द्र की सरकार की पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में बदली हुई सोच को स्थापित करते हैं। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक ताने-बाने की विशालता तथा उसके बहु-विध रंग जो हमारे भारत की कालजयी ऋषि-संस्कृजति, कृषि-संस्कृाति, गौ-गौरी-गाँव को समृद्ध करते है उसके सशक्तिकरण की मौन साधना में लगे साधकों का सम्मान सरकार के बदलते वैचारिक मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। ■

(लेखक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सलाहकार सदस्य हैं।)

दिल्ली की हिंसा संयोग है या सुनियोजित षड्यंत्र

देश में किसान आंदोलन पिछले कुछ महीनों से चल रहा है जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ दिल्ली की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों से भी किसान आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाये गए कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत हैं ।न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग को लेकर सरकार से बातचीत हुई और सरकार ने आश्वासन दिया कि एमएसपी समाप्त नहीं किया जाएगा लेकिन सरकार से अपनी बात मनवाने के बाद किसान इस पूरे बिल को हीखत्म करने पर अड़े हुये हैं। किसान आंदोलन को धार देने व कृषि कानून वापस लेने के लिए पुलिस ने किसानों को सशर्त ट्रैक्टर रैली निकालने की मंजूरी दे दी । परंतु किसान आंदोलन की आड़ में सुनियोजित तरीके से देश को अशांत करने के लिए जिस प्रकार की हिंसा व उपद्रव किया गया वो बेहद शर्मनाक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान प्रदर्शनकारियों ने नियमों को धता–बताते हुए तय रूट से अलग ट्रैक्टर रैली निकाली और पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए सेंट्रल दिल्ली में प्रवेश कर गए । दिल्ली की सड़कों पर किसानों ने जिस प्रकार तांडव और उत्पात मचाया उससे पूरा देश शर्मसार है । इतना ही नहीं उपद्रवी तत्वों ने लाल किले परिसर में जमकर हिंसा की और उसके बाद लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बराबर में सिखों के धार्मिक झंडे निशान साहिब को फहराया। किसानों के इस कृत्य से आम जनमानस में भारी आक्रोश है । 26 जनवरी के दिन घटी घटना/हिंसा संयोग है या सुनियोजित षड़यंत्र?इस विषय पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के संवाददाता उत्कर्ष श्रीवास्तव ने युवाओं से बातचीत की और उनके विचार जाने–

मेरे परिवार ने पीढ़ियों तक किसानी की है और आज भी ये परंपरा चली आ रही है । किसान ऐसा नहीं होता, जैसा आज दिख रहा है । शांतिपूर्वक आन्दोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी करना ये अराजक तत्वों का काम है । किसान आंदोलन के पीछे अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों ने अति उत्साह में आकार जो दुस्साहस किया है उससे देश का हर आम नागरिक व्यथित है । लोगों में गुस्सा है क्योंकि ये बात सिर्फ गुंडागर्दी की नहीं है लाल किले में जो कुछ हुआ है वो देशद्रोह की श्रेणी में आने वाला कृत्य है।

- **दीपेश शर्मा,** रीवा, मध्यप्रदेश

बदलते वक्त की मांग ही परिवर्तन है और इसी क्रम में यदि कृषि क़ानूनों में संशोधन हो रहा है तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों?और यदि तकलीफ है तो सरकार से सीधे बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकालने कि कोशिश करना चाहिए लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है । सरकार बात करने को तैयार बैठी है और किसान अपनी बातों पर अड़े हुये हैं।बेशक इस बिल में कुछ ऐसी बातें है जो किसानों के हित में नहीं हैं, लेकिन उसपर किसान और सरकार दोनों को मिलकर बात करनी पड़ेगी । उपद्रव या हिंसा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

- **मीनाक्षी राय,** नवादा , बिहार

आंदोलन करना तो सही है परंतु क्या ये सब वास्तव में किसान हितों के लिए किया जा रहा है ? पहले शांतिपूर्क आंदोलन करना और फिर शक्ति प्रदर्शन के नाम पर ट्रैक्टर परेड निकालना और उसके बाद अराजकता पैदा करके सड़कों पर खुलेआम हिंसा करना वो भी उसी दिन, जिस दिन हमारा गणतन्त्र दिवस है । ये पूरा घटनाक्रम साफ साफ दर्शाता है कि किसान आंदोलन में किसान हितों की बातें शामिल नहीं है। ये बस एक राजनीतिक स्टंट है जिसे सभी मोदी विरोधी नेता मिलकर करवा रहे हैं।

- **निष्ठा सिंह,** आजमगढ़ , उत्तर प्रदेश

किसान बिल में एमएसपी को लेकर जो असहमति थी उसपर सरकार ने आश्वासन दे दिया है लेकिन पूरे के पूरे कानून को ही वापस करने की मांग करना सरासर गलत है । लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के यहां से जिस बिल को समर्थन मिला हो उसे एकदम से बिना किसी ठोस वजह के वापस कर लेना कैसे संभव है ? मेरे हिसाब से इस कानून में जिन बातों पर असहमति है उस पर सरकार से बातचीत करके आंदोलन जल्द से जल्द खत्म करना ही सही कदम होगा । नहीं तो बेवजह सड़कों पर बैठकर सरकार को कोसने से कुछ नही होने वाला।

- **नवनीत,** जींद, हरियाणा

शांति पूर्वक चल रहे किसान आंदोलन ने अचानक से हिंसात्मक रुख कैसे ले लिया, ये हरकतें देश के किसान तो नहीं कर सकते । ये कहना बिलकुल गलत नहीं है कि खालिस्तानी समर्थक भी इस आंदोलन से जुड़े हैं । आंदोलन स्थलों पर खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह की फोटो के साथ प्रदर्शन करना यह साफ दिखाता है कि किसान आंदोलन को सामने रखकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश पूरे तरीके से सुनियोजित घटना थी । लाल किले में सैकड़ों पुलिस वालों मार मारकर घायल करने वाले कहीं से किसान नहीं दिख रहे थे । ये देश-विरोधी लोगों की हरकतें हो सकती हैं ।

- **अमन कुमार,** दिल्ली

युवा दिवस की झलकियां

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 MARCH, 2021
DATE OF PUBLISHING: 8 MARCH, 2021

POSTAL REGD. NO.: DL(C)-11/1409/2020-2022
POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI

GIVE YOUR BRAND
A UNIQUE IDENTITY

HERE IS THE DESTINATION

DOT COMMUNICATIONS

CREATING
BENCHMARK
IN ADVERTISING
SINCE 1991

Our Services :

- PR Management
- Branding
- Events
- Exhibitions
- Print Media
- Outdoor Media
- Social & Digital Media
- Radio & TV
- Film Production
- Print Production
- Novelty Items

Our Strengths :

- INS Accredited Advertising Agency
- PAN India Presence
- Delivering best results
- Satisfied clients

Dot Communications

Regd. Office: 209-210, 2nd Floor, Gagan Deep Building, Rajendra Place, New Delhi - 110 008
Phone: 011-25713597-99, Fax: 011-25713598, Mobile: 9871223537 / 9310223537 / 8447471305
• E-mail: dotcommunication01@gmail.com • Website : www.dotcommunications.in

Branches : • Agra • Ahmedabad • Bhopal • Chandigarh • Dehradun • Gorakhpur • Guwahati • Jaipur • Jammu • Kanpur • Lucknow • Mumbai • Prayagraj • Patna • Ranchi • Secunderabad • Varanasi